आज का विचार
जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है आपका आत्म-संयम, जो आपको हरसंभव परिस्थिति में स्थिर रखता है।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | बुधवार, 4 फरवरी, 2026 | वर्ष 24, अंक 29, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

2027 में पंजाब में बनेगी भाजपा सरकार, केंद्र की सभी योजनाएं होंगी लागू : नायब सिंह सैनी

पंजाब-हरियाणा एक परिवार- एक संस्कृति और एक संस्कार, मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना- बातें ज्यादा, काम शून्य

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली से जो योजनाएं हरियाणा व अन्य राज्यों में लागू है वह सभी योजनाएं यहां पर लागू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात मंगलवार को नाभा स्थित हीरा महल में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा की छत व वेड़ा भी एक ही है। हमारी संस्कृति व संस्कार सब एक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी-बड़ी बातों को समझ चुके है, ये लोग बातें बहुत करते है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते, लोग इनसे तंग आ चुके है। पंजाब में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सुरक्षित नहीं है, अखाडों में पहलवानों पर गोलियां चलाई जा रही है, इतना ही नहीं चोरियां भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के शासन काल से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यह आज चरम सीमा पर है। यदि कोई रजिस्ट्री करवानी होती है या फिर किसी फॉर्म पर साइन करवाने पड़ते है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी द्वारा चार सालों के दौरान पंजाब में किए गए वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा में

संकल्प पत्र के तहत जो भी वायदें किए गए थे उन्हें पूरा करने काम किया गया है। पंजाब में 1100 रुपए प्रति माह महिलाओं देने की बात कहीं गई थी, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा मे महिलाओं को 2100 रूपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम किया जा रहा है। हरियाणा में गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पंचायती भूमि पर जिस व्यक्ति का 20 वर्षो से कब्जा है उसे नियमानुसार मालिकाना हक देने का काम भी किया गया है, जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पर मकान सम्बधित केस कानूनी प्रक्रिया में चल रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, इसके साथ ही यदि किसानों को अपनी फसल जैसे आलू व अन्य सब्जियां, बाजरे आदि को बाजार भाव कम मिलता है तो उसे भावांतर भरपाई योजना के तहत कवर करने का काम किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब में आए थे और उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से रखने की घोषणा की। इससे करोड़ों अनुयायियों को सम्मान मिला है। साथ ही उन्होंने जालंधर, लुधियाना व अमृतसर को औद्योगिक हब बनाने की बात कहीं है और इस कार्य को पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही मजबूती के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के यह कार्य होता है। पंजाब में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज व हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया था।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

लोकसभा: हंगामें के चलते कामकाज प्रभावित, 8 विपक्षी सांसद निलंबित

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में हुआ खूब हंगामा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

लोकसभा में मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर हंगामा होता रहा और इसके चलते सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। सुबह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर और बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को सत्ता पक्ष के लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में कुछ सांसदों ने आसन (अध्यक्षीय चेयर) की ओर कागज फाड़कर फेंके। बाद में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के प्रस्ताव लाने के बाद 7 कांग्रेस और 01 माकपा सदस्य को सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

निलंबित किए गए सांसद- मणिकम टैगोर (कांग्रेस), अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (कांग्रेस), गुरजीत सिंह औलजा (कांग्रेस), हिबी ईडेन (कांग्रेस), डॉ. प्रशांत यादव राव पाडोले (कांग्रेस), दीन कुरियाकोसे (कांग्रेस), किरण कुमार रेड्डी (कांग्रेस) और एस. वेंकटेशन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)।

रिजिजू ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इन सांसदों ने सदन और अध्यक्ष की गरिमा के प्रति गंभीर अशोभनीय आचरण किया है। इन सदस्यों ने महासचिव की मेज तथा अन्य अधिकारियों की मेज तक पहुँचकर अध्यक्ष की ओर कागज फेंके। अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने के पश्चात, नियम 374(2) के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव स्वीकृति के दौरान भी कुछ सदस्यों ने कागज फाड़ कर फेंके।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मंगलवार को एक बार फिर राहुल गांधी के वक्तव्य में पूर्वी लद्दाख का विषय आने पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष का कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष के व्यवस्था देने के बावजूद राहुल गांधी फिर से वही मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं, विपक्ष का कहना था कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी इसी कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।

राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य की शुरूआत एक पत्रिका के एक लेख को सत्यापित करने से की। उन्होंने उसकी प्रति भी सौंपी। लेख पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित था। इसके बाद उन्होंने इससे जुड़ा विषय सदन में उठाना चाहा। राहुल के वक्तव्य पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेता की बात सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन वे जिस विषय संदर्भ दे रहे हैं, अध्यक्ष पहले ही उसपर निर्णय दे चुके हैं। रिजिजू ने कहा कि जब किसी विषय पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो और वही विषय कल संदर्भित किया गया हो तो उसी विषय को फिर से परोक्ष रूप से उद्धृत नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है।

राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों ने इसपर आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोल रहे हैं। वे लद्दाख से लगती भारतीय सीमा पर बात रख रहे हैं। हालांकि सत्तापक्ष की तरफ से इसपर आपत्ति जाहिर की गई। पीठासीन अधिकारी ने राहुल के स्थान पर अन्य वक्ताओं को चर्चा में भाग लेने और अपना वक्तव्य देने के लिए कहा। इसी बीच कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया।

इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही सुबह दो बार स्थगित हुई। इसके बाद दोपहर 02 बजे प्रारंभ होने के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि वे केवल इसी विषय पर अपनी बात रखें।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सुबह लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आसन के समीप पहुंच गए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई।

भारत में सामाजिक न्याय की नींव संवैधानिक मूल्यों पर आधारित: सावित्री ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
न्यूयॉर्क

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्मृति सावित्री ठाकुर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक संरक्षण की नींव संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है और यह देश की दीर्घकालिक परिकल्पना विकसित भारत 2047 के अनुरूप है।

सावित्री ठाकुर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग (सीएसओसीडी) के 64वें सत्र में भारत की अध्यक्षता की। कार्यकम में उन्होंने राष्ट्रीय देते हुए कहा कि भारत मेंशिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और लड़कों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए बेहतर स्कूल अवसंरचना और दूरदराज क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। पाइप से पेयजल, स्वच्छ रसोई ईंधन और स्वच्छता सुविधाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार से महिलाओं और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, जिनसे महिलाएं उद्यमिता और ऋण योजनाओं की प्रमुख लाभार्थी बनी हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित हेल्पलाइन और एकीकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से देशभर में संरक्षण और सहायता तंत्र को मजबूत किया गया है।

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्मृति सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सत्र में समावेशी और अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत को बताते हुए कहा कि सरकार समग्र सरकारी और समग्र सामाजिक दृष्टिकोण के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।

उन्होंने कहा कि मातृ, शिशु स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाओं के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, असंगठित श्रमिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी विस्तार किया गया है।

उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। वैश्विक चुनौतियों पर बोलते हुए भारत ने बहुपक्षीय सहयोग, क्षमता निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने का समर्थन किया।

उल्लेखनीय कि सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र की अध्यक्षता यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत क्रिस्टीना हायोविशिन ने की। सत्र को संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे. मोहम्मद, महासभा की अध्यक्ष एच.ई. एनालेना बेयरबॉक, ईकोसॉक के अध्यक्ष एवं नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा, डीईएसए की सहायक महासचिव ब्योर्ग सैंडक्येर तथा एनजीओ समिति ऑन सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्ष गिलियन डीह्लसूजा-नजरेथ ने संबोधित किया। इस सत्र में 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने भाग लिया।

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया सात माह बाद नाभा जेल से रिहा

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला की जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मंगलवार को करीब सात माह बाद नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद मजीठिया के वकील आज जेल पहुंचे और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

आम आदमी पार्टी मजीठिया को जेल में बंद करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रही है। पंजाब से

लेकर गुजरात तक पार्टी मंचों से कहती रही कि जिनका नाम लेने से भी लोग डरते थे, उन्हें हमने जेल भेज दिया। इस बीच मंगलवार को नाभा जेल से बाहर आते ही मजीठिया ने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मूंछों को ताव दिया। उनके साथ उनकी पत्नी गनीव कौर भी मौजूद थी।

मजीठिया ने कहा कि धन-धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। गुरु साहिब की अपार कृपा। जितना सरकार ने दबाया, उतनी ताकत मिली। दिल्ली हुक्मरानों के साथ ईंट से ईंट टकरानी है। मुझे इस बात की प्रेरणा मिली है।

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पिछले साल 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वह जेल में ही थे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संसद में बयान देंगे पीयूष गोयल

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बने संशय को दूर करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को संसद में एक बयान दे सकते हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। सोमवार देर रात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक्स पर पोस्ट के बाद इस समझौते को लेकर तमाम तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी के साथ भारत पर लागू टैरिफ घटाकर तत्काल 18 फीसदी करने की भी घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर वाशिंगटन में हैं।

सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मुंबई से नई दिल्ली लौट रहे हैं और संभवतः वह संसद में इस समझौते को लेकर बयान देंगे जिसमें समझौते की रूपरेखा साफ हो जाएगी।

जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, सामानों पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी पर लाएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ह्यमेड इन इंडियाह्न उत्पादों पर अब 18 फीसदी का कम शुल्क लगेगा।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ह्यएक्सह्न पोस्ट पर लिखा, ह्लये समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल कामगारों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा, जिससे वे दुनिया के लिए ह्यमेक इन इंडियाह्न, दुनिया के लिए डिजाइन इन इंडिया और दुनिया के लिए इनोवेट इन इंडिया कर सकेंगे। इससे भारत को अमेरिका से तकनीक हासिल करने में मदद मिलेगी।

भारत आज ग्लोबल फार्मास्युटिकल हब के रूप में स्थापित : जेपी नड्डा

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

उत्तर प्रदेश को दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित होटल ताज में आयोजित वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम ह्यउत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव-1ह्न का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर देश-विदेश से आए निवेशक, फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, चिकित्सा विशेषज्ञ और नीति निमार्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज ग्लोबल फार्मास्युटिकल हब के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। उन्होंने बताया कि विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जेनरिक दवाएं और करीब 60 प्रतिशत वैश्विक वैक्सीन मांग की पूर्ति भारत करता है। भारतीय फार्मा उत्पादों का निर्यात आज 200 से अधिक देशों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान, रिसर्च, विकास और निर्यात तक पूरे फार्मा सेक्टर को मजबूत किया गया है।

जेपी नड्डा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की गई है, जिसे आगामी पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक दवा निर्माण हब के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार निवेशकों को भूमि, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व स्तर पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भारत की फार्मा और स्वास्थ्य क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने बताया कि देश में स्वास्थ्य ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है और आज 800 से अधिक मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। साथ ही एमबीबीएस सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश फार्मा उद्योग के लिए देश का सबसे बड़ा बाजार है। राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क सहित औद्योगिक बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के 55 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन, मजबूत लॉजिस्टिक्स और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में 16 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं, जिनमें चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र के लिए स्पष्ट और प्रभावी योजनाएं मौजूद हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर निवेशकों को त्वरित स्वीकृति प्रदान की जा रही है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में अराजकता, पलायन और अवैध वसूली का माहौल था, लेकिन अब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और प्रदेश विकास के नए पथ पर अग्रसर है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश में दवा उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित दवाओं को सरकार प्राथमिकता के आधार पर खरीदेगी और उन्हें मरीजों की सेवा में लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं। पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान प्रदेश की पहचान हैं। राज्य में साढ़े तीन हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 200 विशिष्ट चिकित्सालय तथा सभी जिलों में जिला अस्पताल संचालित हैं। हर वर्ष 50 करोड़ से अधिक मरीजों का ओपीडी में उपचार किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीते आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव आया है। 75 जिलों को 24 घंटे बिजली, सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ा गया है। एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र उद्घाटन होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब माफियाविहीन है और कानून का राज स्थापित हुआ है। रेल और सड़क नेटवर्क मजबूत हुआ है और उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

इस कॉन्क्लेव में दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और चिकित्सा विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कई फार्मा कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में दवा उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

डीएचएस में 300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा बनेगा: सुक्खू

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (डीएचएस) में 300 डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा या पीजी कोर्स के लिए जाने वाले डॉक्टरों के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अप्रैल माह से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू करेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में नैदानिक सेवाओं को मजबूत करना और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और जरूरत के अनुसार नए पद भी सृजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में भी जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में पहले से ही रोबोटिक सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ह्यआदर्श स्वास्थ्य संस्थानोंह्न को भी सशक्त बना रही है, ताकि लोगों को उनके घर-द्वार के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों के लिए छोटे बैच बनाए जाएं और किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र न हों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों में नए लेक्चर थिएटरों के निर्माण में भी सहायता करेगी।

अटल टनल के समीप सड़क मार्ग पर आया हिमखंड

एजेंसी (हि.स.)
कुल्लू

दो दिन की धूप के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मंगलवार से लाहुल-स्पीति और मनाली के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लगातार हो रहे हिमपात के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अटल टनल रोहतांग के समीप सीसु में पहाड़ी की तरफ से हिमस्खलन हुआ लेकिन भाग्यशाली रहे कि उस दौरान कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बीआरओ की टीम द्वारा हिमखंड को कुछ ही देर में हटा दिया गया ओर यातायात बहाल हो गया।

मनाली से लाहुल तक कई स्थानों पर हिमखंड गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग और सासे ने एवलांच को लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

भारी बर्फबारी के चलते लाहुल-स्पीति में पहले से बंद सड़क मार्गों को बहाल करने का कार्य प्रभावित हुआ है। रोहतांग दर्रा में अब तक 10 फुट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि बारालाचा और कुंजम दर्रा में 11 फुट से अधिक बर्फ जम चुकी है। अटल रोहतांग टनल के आसपास भी 5 से 6 फुट तक बर्फ जमा होने से आवाजाही पर असर पड़ा है।

ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण जहां हालात गंभीर बने हुए हैं, वहीं कुल्लू, भुंतर और आसपास के निचले क्षेत्रों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और बाजारों में रौनक भी कम नजर आई।

गौरतलब है कि 23 और 24 जनवरी को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। इसके बाद दोबारा शुरू हुए हिमपात से पर्यटन नगरी मनाली सहित कुल्लू जिला एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है, जिससे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। लगातार बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में खुशी का माहौल है। वहीं किसान और बागबान भी इस मौसम को लेकर उत्साहित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बर्फबारी सेब सहित अन्य नकदी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी और आने वाले सीजन में बेहतर पैदावार की उम्मीद बढ़ेगी।

मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और बर्फबारी के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

मंडी के खुराहल और भवाणा में एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत पौधारोपण और प्रशिक्षण शिविर आयोजित

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

बागवानी विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सब-ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत मंडी जिला के सुंदरनगर विकास खंड स्थित खुराहल और भवाणा में वृक्षारोपण अभियान और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। सोहन लाल ठाकुर ने बागवानी विभाग की कार्यप्रणाली और लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि लगभग दो महीने पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन क्लस्टर के भूमि विकास कार्यों का निरीक्षण किया था और विभाग को दो माह के भीतर वृक्षारोपण शुरू करने के कड़े निर्देश दिए थे। विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 19 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिए तैयार कर इस अभियान को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाया है। इस वर्ष क्लस्टर के अंतर्गत कुल 11,875 पौधों का रोपण किया जाएगा। तकनीकी सत्र के दौरान बागवानी विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. वी.पी. बैंस ने किसानों को जापानी फल (पर्सिमन) की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह फल न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, बल्कि बाजार में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए यह भविष्य में बागवानों के लिए आय का एक सशक्त माध्यम बनेगा। वहीं, उप-निदेशक बागवानी डॉ. संजय गुप्ता ने एचपी शिवा परियोजना की बारीकियों को साझा करते हुए बताया कि यह योजना क्लस्टर आधारित खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखती है। शिविर के दौरान विशेषज्ञों द्वारा लाभार्थियों को जापानी फल के पौधों को रोपने की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि का व्यावहारिक प्रदर्शन भी दिया गया ताकि पौधों का बेहतर विकास सुनिश्चित हो सके।

केंद्र के बजट से हिमाचल निराश, राज्यों के अधिकारों पर चोट : प्रो. चंद्र कुमार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार की वित्तीय नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र द्वारा अपनाई जा रही नीतियां संघीय ढांचे की भावना के विपरीत हैं और इससे विशेष रूप से पहाड़ी व संसाधन-संरक्षण करने वाले राज्यों को आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। मंगलवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 1952 से भारत में वित्त आयोग की व्यवस्था लागू है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित होती है। इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन कर उन्हें न्यायसंगत सहायता प्रदान करना रहा है। हर पांच वर्ष में गठित होने वाला यह आयोग राज्यों में जाकर उनके खर्च, आय के स्रोतों और विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करता था।

कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय हित में ग्रीन फेलिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इससे पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को तो लाभ मिला, लेकिन राज्य की एक बड़ी आय समाप्त हो गई। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इस राजस्व हानि की भरपाई के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जंगलों का संरक्षण पूरे देश के हित में है, लेकिन उसका आर्थिक भार केवल हिमाचल जैसे राज्यों पर डालना अन्यायपूर्ण है।

प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं, उत्पादन सीमित है और जनसंख्या कम होने के कारण जीएसटी तथा अन्य करों में राज्य का हिस्सा भी कम बनता है। पर्यटन से होने वाली आय भी मौसमी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत ढांचे का निर्माण मैदानी राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक मंहगा पड़ता है। एक किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए कई किलोमीटर का घुमावदार मार्ग बनाना पड़ता है, जिससे लागत अत्यधिक बढ़ जाती है।

संक्षिप्त-समाचार

शाहपुर में सड़कों, पुलों व भवनों पर व्यय हो रहे 90 करोड़ : केवल सिंह पठानिया

धर्मशाला। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर शाहपुर विश्राम गृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने की। बैठक के दौरान उपमुख्य सचेतक ने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण पर लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। केवल सिंह पठानिया ने ङ्कस्र अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों का सेक्शन-वाइज डाटा तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रभावी और योजनाबद्ध उपयोग किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे बरसात के मौसम में सड़कों को नुकसान न हो और आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न झेलनी पड़े। उपमुख्य सचेतक ने कहा कि कुछ सड़कें जो पिछले कई वर्षों से लंबित थीं, उन्हें वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की सराहना की । उन्होंने सभी विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके।

नशे के मामले में गिरफ्तार आरोपी तीन माह के लिए निवारक हिरासत में

धर्मशाला। पालमपुर पुलिस थाना के तहत फरार चल रहे नशे के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे निवारक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शुभकरण उर्फ शिवु पुत्र राजेश कुमार, निवासी वार्ड नम्बर-2 पालमपुर के विरुद्ध थाना पालमपुर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित चार मामले पंजीकृत हैं, जिनमें उसके कब्जे से चिट्टा तथा चरस जैसे नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई थी। बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी की गतिविधियां जारी रखने के तथ्य सामने आए थे। जिस पर जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा आरोपी शुभकरण उर्फ शिवु के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निवारक हिरासत के सम्बन्ध में 27 दिसम्बर 2025 को प्रोपोजल तैयार करके उच्चाधिकारियों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। जो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, सक्षम अधिकारी ने तीन माह की अवधि के लिए जिला जेल कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए थे लेकिन आरोपी शुभकरण उर्फ शिवु अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चला आ रहा था। फरार चले आ रहे आरोपी शुभकरण उर्फ शिवु को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे तथा एक विशेष गुप्त टीम का गठन करके जिला कांगड़ा व अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी।

डीसी कठुआ ने आईसीडीएस व समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा की

कठुआ। उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने बुधवार डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में आईसीडीएस और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में एडीडीसी, आईसीडीएस व सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारी तथा फील्ड फंक्शनरी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि जिले में 1641 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं और पीएमएमवीवाई के तहत 3915 लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। डीसी ने सभी योजनाओं की शत-प्रतिशत सैचुरेशन पर जोर देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएसएपी, आईएसएसएस, एसएमएएस, एडीआईपी सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और लाभार्थियों तक समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने पर बल दिया।

सीयू में हो रही गुरू तेग बहादुर पीठ की स्थापना : प्रो. बंसल

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पंजाबी एवं डोगरी विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री गुरु तेग बहादुर जी : जीवन, वाणी और शहादत विषयक दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में डा. कृष्णगोपाल सह-सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर पद्मश्री आचार्य हरमोहिंदर सिंह बेदी, कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला द्वारा कुलाधिपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

संगोष्ठी के संरक्षक एवं कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल भी मौजूद रहे। इस मौके पर संगोष्ठी के शुभारंभ पर संरक्षक कुलपति प्रो. बंसल ने कहा कि दो दिवसीय इस संगोष्ठी में कई विद्वान अपने विचार रख रहे हैं। यह विश्वविद्यालय का गौरव का पल है। उन्होंने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दी गई शहादत ने भारत की साझा सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ऐसे अकादमिक आयोजन आत्ममंथन का अवसर प्रदान करते हैं और यह सोचने को प्रेरित करते हैं कि हम आज उनके आदर्शों से क्या सीख सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर जल्द ही विश्वविद्यालय में श्री गुरू तेग बहादुर पीठ शीघ्र खोलने की घोषणा की।

इस मौके पर मुख्य वक्ता डा कृष्णगोपाल सह-सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, धार्मिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा का शाश्वत प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि किसी भी महान व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब उसे उसके समय, परिस्थितियों और सामाजिक संघर्षों के संदर्भ में समझा जाए।

डा. कृष्णगोपाल ने गुरु नानक देव जी से प्रारंभ हुई गुरु परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय समाज को जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठाकर एकता, समानता और मानवता का मार्ग दिखाया। संगत, लंगर और धर्मशाला जैसी संस्थाओं के माध्यम से समाज में आत्मविश्वास और सामाजिक समरसता का निर्माण हुआ, जिसने आगे चलकर अत्याचार के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की नींव रखी। जब मुगल शासन के दौरान जबरन धर्मांतरण और धार्मिक दमन अपने चरम पर था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों सहित समस्त पीड़ित समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह बलिदान किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के अधिकारों की रक्षा के लिए था।

जम्मू-कश्मीर में यह सरकार 'दूरदृष्टिहीन' साबित हो रही: रजनी सेठी

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी ने एनसी सरकार पर झूठे वादों, नाकामियों और जनहितों की पूर्ण उपेक्षा के लिए कड़ी आलोचना की। रजनी सेठी ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की तथाकथित लोकप्रिय सरकार है।

दुर्भाग्य से, दूरदर्शिता और जवाबदेही के साथ शासन करने के बजाय इस सरकार ने खोखले वादों और घोषणाओं के जरिए बार-बार जनता को गुमराह किया है जो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए किए गए थे। घोषणापत्र, जिसने कभी उम्मीद और बदलाव का प्रतीक होने का दावा किया था असल में धोखे का दस्तावेज साबित हुआ है और जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा है।

एनसी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए रजनी ने कहा कि एनसी सरकार की सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवाओं का वादा था। जिसमें स्मार्ट बसें, एसआरटीसी बसें और अन्य सरकारी अधिकृत परिवहन शामिल थे। इस घोषणा को महिलाओं के हितैषी और प्रगतिशील कदम के रूप में पेश किया गया था जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी दैनिक यात्रा को सुगम बनाना था। हालांकि एक साल बीत जाने के बाद भी जमीनी हकीकत इस बात की पूर्ण विफलता को उजागर करती है।

मनन — योजनाओं को लेकर की गई गहन चर्चा

भाजपा जम्मू दक्षिण जिला महिला मोर्चा ने परिचयात्मक-सह-मासिक बैठक का किया आयोजन

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

भारतीय जनता पार्टी जम्मू दक्षिण जिला महिला मोर्चा ने आज त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक परिचयात्मक-सह-मासिक बैठक और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना तथा जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाना था। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अधिवक्ता नेहा महाजन ने की।

कार्यक्रम में भाजपा जम्मू दक्षिण के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह जसरोतिया और भाजपा महिला मोर्चा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की महासचिव और संसदीय क्षेत्र प्रभारी इंजीनियर उर्वशी गुप्ता उपस्थित थीं। बैठक का आयोजन जम्मू दक्षिण जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीतू शर्मा के नेतृत्व में किया गया।

कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त जिला प्रभारी श्रीमती सोनिया ठाकुर और सह-प्रभारी गुरमीत कौर को वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा उनकी जिम्मेदारियों और संगठनात्मक प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता नेहा महाजन ने बूथ स्तर पर लामबंदी और संगठनात्मक विस्तार में महिला मोर्चा की निर्णायक भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और मातृशक्ति के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 7 से 9 फरवरी तक कांगड़ा के दौरे पर

धर्मशाला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 7 से 9 फरवरी तक कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वह विभिन्न बैठकों और पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 7 फरवरी को प्रातः 10: 30 बजे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के पालमपुर ग्रामीण मंडल की बैठक में भाग लेंगे तथा उसके उपरांत दोपहर 1:30 बजे पालमपुर शहरी मंडल की बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बताया सांय 5:00 बजे जयराम ठाकुर पदमश्री डॉ पीएल गौतम सेवानिवृत वाईस चांसलर से मुलाकात करेंगे तथा रात को पालमपुर में ही रुकेंगे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रातः 9 बजे जस्टा रिसोर्ट में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे तथा उसके बाद 10 बजे नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के बाबा बड़ोह के लिए रवाना होंगे जहां वह प्रातः 11 बजे बाबा बड़ोह मंडल की बैठक में भाग लेंगे। त्रिलोक कपूर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोपहर डेढ़ बजे बाबा बड़ोह से देहरा के लिए रवाना होंगे। वहीं शाम 3 बजे जिला कार्यालय देहरा में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अभ्यास वर्ग का समापन करेंगे। इसके बाद वह सांय 5 बजे प्रस्थान देहरा से धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को प्रातः 11 बजे जयराम ठाकुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा बाद में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर बाद शाहपुर भाजपा मंडल की बैठक में भाग लेंगे।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

समाज के लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर दें ध्यान, इसी से समाज, प्रदेश व देश का नाम होता रोशन: राजेश नागर

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गुर्जर समाज के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने पर ध्यान दें। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से समाज, प्रदेश व देश का नाम रोशन होता है। शिक्षित व्यक्ति समाज को ऊपर तक लेकर जाने में अहम भूमिका निभाता है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्यमंत्री राजेश नागर मंगलवार को गुर्जर धर्मशाला के 44 वें स्थापना समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। राज्यमंत्री राजेश नागर ने धर्मशाला को अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही समाज के किसी भी कार्य के लिए हर समय सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। राज्यमंत्री राजेश नागर ने कहा कि समाज के लोगों की धर्मशाला के साथ लगती रेलवे की भूमि, कोचिंग सेंटर के लिए सेक्टर में प्लाट की मांग को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखकर पूरा करवाया जाएगा। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सीएम सिटी है। यहां पर होने वाले किसी भी कार्य के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मना नहीं करते। गुर्जर समाज द्वारा रखी गई इन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की गुर्जर धर्मशाला सबसे बड़ी धर्मशाला है। जो अन्य धर्मशालाओं में समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। आज तक इस धर्मशाला में कभी भी चुनाव नहीं हुआ है। दूसरी धर्मशालाओं में जब चुनाव की बात होती है तो कुरुक्षेत्र की धर्मशाला का नाम लेकर उन्हें शांत किया जाता है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मरणोपरांत शोक को 13 दिनों तक मनाया जाता है, जो उस समय की प्रथा जब सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के पास संपर्क करने के लिए फोन व अन्य फास्ट सुविधा नहीं होती थी। सभी जानकार 13 दिनों के अंदर पहुंचकर शोक व्यक्त करते थे। आज दिन के दिन ही सूचना सभी तक पहुंच जाती है। ऐसे में इस शोक अवधि को 7 दिनों तक किया जाना चाहिए। कई समाज के लोग तो 3-4 दिन तक सीमित रखते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही इस परिवारजन 13 दिनों तक अपनी रस्मों को निभाते रहें। हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि वर्ष 1983 में गुर्जर धर्मशाला के रूप में लगा पौधा अब वट वृक्ष बन चुका है। इस धर्मशाला में हमारे बुजुर्गों ने अपने संस्कार और प्यार को एक-एक ईंट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि शहर में जब भी कोई काम होता है तब सबसे पहले धर्मशालाओं को याद किया जाता है और धर्मशालाएं सरकार व प्रशासन का उम्मीदों से भी बढ़कर सहयोग करती हैं। इस धर्मशाला की सभी मांगों को राज्यमंत्री राजेश नागर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचाया जाएगा। गुर्जर धर्मशाला के प्रधान ऋषिपाल कसाना ने कहा कि धर्मशाला में अब तक सभी प्रधानों ने समाज के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कार्य किया है। धर्मशाला में युवाओं के लिए छात्रावास तैयार किया है। इसके अलावा कंप्यूटराइज लाइब्रेरी बनाई हुई है। धर्मशाला में रहने व खाने की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने समाज के लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे सहयोग से सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय प्रधान अनंत राम ने भी संबोधित किया। गुर्जर नेता राव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धर्मशाला गुर्जर समाज की सबसे बड़ी धर्मशाला है। धर्मशाला का नाम राष्ट्रीय गुर्जर धर्मशाला रखा जाना चाहिए। इस बात पर समारोह में मौजूद सभी लोगों ने सहमति जताई। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान अनंत राम, चेयरमैन राजपाल तंवर, ब्लॉक समिति पिहोवा चेयरपर्सन पिंकी देवी, एडवोकेट ज्ञानचंद कसाना, नरेश आर्य, ओमप्रकाश राठी, प्रेमचंद गांगल, अजमेर सिंह अन्य मौजूद रहे।

15 दिन के नेशनल कंटेम्परारी स्टोन कार्विंग स्कल्पचर सिंपोजियम में आज के जमाने की बनाई 16 शानदार पत्थर की मूर्तियां : धूमन सिंह किरमच

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि पवित्र पिहोवा तीर्थ इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2026 के एक खास हाईलाइट के तौर पर हुए 15 दिन के नेशनल कंटेम्परारी स्टोन कार्विंग स्कल्पचर सिंपोजियम का सफलता पूर्वक समापन हुआ। इस सिंपोजियम में आज के जमाने की 16 शानदार पत्थर की मूर्तियां बनाई गईं, जिन्हें 15 दिनों तक दिन-रात की कड़ी मेहनत से बड़े-बड़े प्राकृतिक काले मार्बल ब्लॉक से बहुत ध्यान से तराशा गया। जिसे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरकार के आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच सोमवार को सरस्वती तीर्थ पिहोवा पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान सभी मूर्तिकारों को सम्मानित भी किया। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि सिंपोजियम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स, पिहोवा तीर्थ में एक कंटेम्परारी स्कल्पचर पार्क बनाने की अगुवाई कर रहे हैं, जहां ये मूर्तियां हमेशा के लिए लगाई और दिखाई जाएंगी। यह प्रस्तावित पार्क सालभर चलने वाले क्रिएटिव हब के तौर पर काम करेगा, जो युवा, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कलाकारों को ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स देगा। यह पारंपरिक पत्थर की नक्काशी टेक्नीक और मॉडर्न आर्टिस्टिक इनोवेशन के मेल को बढ़ावा देगा। कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सरस्वती महोत्सव 2026 के हिस्से के तौर पर इस सिंपोजियम से पेहोवा, कुरुक्षेत्र और हरियाणा को लंबे समय तक चलने वाले फायदे हुए हैं। इस मौके पर सीईओ कुमार सुप्रवीन, तहसीलदार पूनम सोलंकी, नगर पालिका अध्यक्ष आशीष चक्रपाणि, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेंद्र ढींगरा, वरिष्ठ भाजपा नेता युधिष्ठिर बहल, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड सदस्य रामधारी शर्मा, भाजपा नेता राकेश पुरोहित, सुदर्शन मुरार, डीपी दस्तूर, अरूण ठकुराल, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड विनोद कुमार, बलबीर सिंह दत्ता, मान की बात जिला सचिव प्रमुख हान्नु चक्रपाणि, बंटी दिवाना, लाड़ी पाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

सूरजकुंड मेले में मिलेट्स फूड स्टॉल बन रही पर्यटकों की पहली पसंद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में मोटे अनाज (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की पहल को जमीनी स्तर पर साकार करने का कार्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले के गांव डवाना की अनिता देवी मोटे अनाज से बने उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डवाना एग्रो किसान उत्पादक संगठन द्वारा तैयार किए गए मिलेट्स उत्पाद इन दिनों फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। ह्यलोकल फॉर ग्लोबल - आत्मनिर्भर भारत की पहचानह्ल थीम के तहत आयोजित इस मेले के फूड कोर्ट में संगठन ने ह्यमिलेट्स फूडह्ल के नाम से स्टॉल लगाई हुई है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अस्वस्थ जीवनशैली के कारण लोग तेजी से जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अच्छी सेहत में 70 से 80 प्रतिशत भूमिका खानपान की होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने मोटे अनाज को फिर से लोगों की थाली तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्टॉल पर बाजरा लड्डू, रागी लड्डू, बाजरा नमकीन, बाजरा मठरी, बाजरा खिचड़ी, बाजरा आटा, बाजरा बिस्कुट, स्पेशल मिलेट्स थाली, मोरिंगा पराठा, बाजरा पिज्जा, आदि शामिल है।

गुजरात के किसान एवं कल्याण मंत्री जीतूभाई वघानी पहुंचे गुरुकुल

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म पर राज्यपालश्री आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में हो रही प्राकृतिक खेती किसी अजूबे से कम नहीं है। हरियाणा की भूमि पर जहाँ ड्रेगन फ्रूट, खजूर, सेब और चने की फसलें आमतौर पर नहीं होती मगर गुरुकुल के फार्म पर यह करिश्मा प्राकृतिक खेती से सम्भव हो रहा है। उक्त शब्द गुजरात के कृषि एवं किसान कल्याण व पशुपालन मंत्री श्री जीतूभाई वघानी ने गुरुकुल के फार्म का दौरा करने के उपरान्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि आचार्य देवव्रत जी आधुनिक युग के कृषि-ऋषि हैं जिनके प्रयासों से आज देश भर में किसान लाखों की संख्या में जहरमुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाकर देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व गुरुकुल पहुंचने पर राज्यपालश्री आचार्य देवव्रत जी ने मंत्री महोदय का बुके देकर स्वागत किया। उनके साथ कृषि राज्यमंत्री श्री रमेश भाई कटारा, कृषि विभाग के प्रिंसीपल सेकेटरी आर. सी. मीणा, कृषि निर्देशक आर. पी. राजपूत सहित अन्य कृषि विषेषज्ञ भी गुरुकुल के फार्म का दौरा करने हेतु गुरुकुल पहुंचे।

आचार्यश्री की मौजूदगी में मंत्री महोदय ने फार्म पर पत्तागोभी, मटर, गाजर की फसलों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही कच्ची मटर और पत्तागोभी को मौके पर तोड़कर उसके प्राकृतिक स्वाद का आनन्द लिया। गुरुकुल के लगभग 15 फीट ऊंचे गन्ने की भी मंत्री महोदय ने खूब तारीफ की। श्री जीतूभाई वघानी सहित अन्य कृषि विशेषज्ञों ने फार्म पर हरी सब्जियों व गेहूं और चना की सहफसलों के मॉडल भी देखे, जिन्हें गुजरात में भी लागू करने के निर्देश मंत्री महोदय ने अधिकारियों को दिये। मंत्री महोदय ने गुरुकुल के फार्म पर स्थित क्रेशर पर गरमा-गरम प्राकृतिक गुड़ का भी स्वाद चखा'

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपालश्री आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्राकृतिक खेती मिशन से देश भर में बड़ी संख्या में किसान जुड़ रहे हैं। केवल गुजरात में ही लगभग 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती देशी गाय पर आधारित है, ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ इस खेती से गाय माता का भी संरक्षण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पिछले 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती की जा रही है, अब यहां के खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन रीच केटेगरी में है, अर्थात्यहां की भूमि इतनी उपजाऊ हो चुकी है कि यहां पर गेहूँ, चावल व अन्य फसलों का उत्पादन रासायनिक खेती से भी ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आज की जरूरत ही नहीं बल्कि पर्यावरण और धरती को बचाने का एकमात्र विकल्प है। देश के किसान भी इस बात को बखूबी जा चुके हैं और बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं।

संक्षिप्त-समाचार

किसानों को मिट्टी जांच के आधार पर फसल की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित करें: कृषि मंत्री

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा बागवानी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को मिट्टी जांच के आधार पर फसल की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे अच्छी पैदावार ले सकें। श्री राणा आज यहां कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक , बागवानी निदेशालय के महानिदेशक श्री रणबीर सिंह , मिशन निदेशक श्री जोगिंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करनी चाहिए , इसके बाद जिन पोषक तत्वों की जरुरत हो उनको पूरा करने तथा उसी आधार पर फसल की बिजाई करने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक ही प्रकार की फसल की बार -बार बिजाई करने से भूमि में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उस जमीन के बंजर बनने की संभावना होती है , ऐसे किसानों को मिटटी जांच के बाद मोबाइल फोन पर मैसेज भेज कर सतर्क करने तथा सही फसल की बुआई करने की सलाह देने के भी निर्देश दिए। श्री राणा ने अधिकारियों को फसलों का नया फसल-चक्र आजमाने का भी सुझाव दिया ताकि कम पानी में फसल तैयार हो सके और किसानों को उस फसल से अच्छी आमदनी भी हो सके। उन्होंने कृषि बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की और किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करने के निर्देश दिए।

पेपरलेस रजिस्ट्री की सफलता के बाद, हरियाणा मार्च के आखिर तक फरीदाबाद से फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट करेगा शुरू

चंडीगढ़। प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद हरियाणा सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ह्यफेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टमह्ल का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट राज्य का पूरी तरह से डिजिटल, फेसलेस और नागरिक-केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता को और बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार है जो नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा। इस अवधि में इसकी कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाएगी और परिणामों के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। नई प्रणाली के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिससे तेज प्रोसेसिंग, बेहतर दक्षता और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। इससे संपत्ति लेन-देन अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बन सकेगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह फेसलेस सिस्टम भारत सरकार के टी३ क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जिससे उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सभी अप्रूव्ड फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को पायलट फेज के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि कुछ नॉन-क्रिटिकल फीचर्स को यूजर फीडबैक और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर बाद में शामिल किया जा सकता है। परियोजना के सुचारू संचालन के लिए राजस्व विभाग एवं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

जेसीआई कुरुक्षेत्र के प्रधान बने आशीष मल्होत्रा, नई टीम का शपथ समारोह

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल (जेसीआई) संगठन की कुरुक्षेत्र इकाई की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया जिसमें सभी पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। पिपली रोड स्थित एक निजी होटल में 46वें शपथ ग्रहण समारोह में जेसीआई के नए प्रधान एडवोकेट आशीष मल्होत्रा और उनकी पूरी टीम ने शपथ ग्रहण की। संस्था के पूर्व प्रधान संदीप मारवाह ने नए प्रधान एडवोकेट आशीष मल्होत्रा को पदभार सौंपा। इस भव्य कार्यक्रम ने जिला एवं सत्र न्यायधीश दिनेश कुमार मित्तल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उनके अलावा जोन अध्यक्ष अमित गौड़ ने भी विशेष रूप से भाग लिया।

नवनियुक्त प्रधान एडवोकेट आशीष मल्होत्रा को संस्था की प्रथम महिला एडवोकेट पूर्णिमा मल्होत्रा की उपस्थिति में अमित गौड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत नए प्रधान एडवोकेट आशीष मल्होत्रा ने अपनी टीम के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उनकी टीम में सुमित बंसल को सचिव और डॉक्टर मनीष मदान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। जबकि जेसीआई महिला विंग में जैसरीट एडवोकेट पूर्णिमा को अध्यक्ष एवं रजनी अरोड़ा को सचिव की जिम्मेवारी दी गई है।

पूर्व प्रधान संदीप मारवाह ने अपने कार्यकाल में करवाए सामाजिक कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि सामाजिक संस्था जेसीआई कुरुक्षेत्र द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य प्रशंसनीय हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि बेहतर समाज के निर्माण में सभी मिलकर समाज सेवा की भावना से अपना योगदान दें। उन्होंने नई टीम को बधाई दी।

कार्यक्रम का मंच संचालन एडवोकेट पूर्णिमा मल्होत्रा और डॉ. मोनिका चोपड़ा ने किया। इस मौके पर लायंस क्लब के प्रधान विशाल शर्मा, गगनदीप सिंह, जेसीआई कुरुक्षेत्र के सदस्य चन्द्रेश अरोड़ा, दीपक चोपड़ा, सुरिंदर सुधा, दीपक सिंगला, नवकेतन गोयल बब्बी, रणवीर सिंह, राजेश आनंद, संजीव जुल्का, विवेक भारद्वाज डब्बू, डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. रमन अनेजा, डॉक्टर माधविका मदान, सीमा बंसल, हरजिंदर कौर, चारू बजाज, सोनिका भारद्वाज व अन्य मौजूद रहे।

पूर्व में की सरपंची की पेंशन मिलने की सूचना मिलने पर खुशी में खूब हंसे रामचंद्र और डीसी का किया शुक्रिया अदा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

गांव झिमरेहड़ी-1 निवासी एवं पूर्व सरपंच रामचंद्र खुशी में उस समय अपनी हंसी को नहीं रोक पाए जब उन्हें पता चला कि वो हर माह पूर्व में की सरपंची की पेंशन अपने खाते में पा रहे हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का रामचंद्र ने बार-बार शुक्रिया अदा किया और हंसते हुए अपनी खुशी को जताया। ये मौका था सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर का।

सोमवार को झिमरेहड़ी-1 निवासी पूर्व सरपंच रामचंद्र गांव की फरियाद लेकर समाधान शिविर में पहुंचे थे। उन्होंने गांव की समस्या के बारे में उपायुक्त को अवगत करवाया और खुद का पूर्व सरपंच होने का परिचय दिया। इस दौरान समस्या सुनते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने रामचंद्र से पूछा कि आपको सरपंची की पेंशन मिल रही है या नहीं ले रहे। जवाब में रामचंद्र ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उपायुक्त ने पंचायत विभाग से मौके पर ही रामचंद्र का डाटा चैक करवाया। पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने पूर्व सरपंच रामचंद्र के खाते में पेंशन पाने का पूरा डाटा प्रस्तुत किया।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पूर्व सरपंच रामचंद्र को बधाई देते हुए कहा कि आपको तो पूर्व सरपंच होने की पेंशन खाते में मिल रही है। रामंचद्र को इस बारे में यकीन नहीं हुआ तो उपायुक्त ने उन्हें उनका खाता नंबर व अन्य डाटा की विस्तृत जानकारी दी तो रामचंद्र बहुत खुश हुआ और खुशी की हंसी को रोक नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त का बार-बार शुक्रिया अदा किया।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व सरपंचों के लिए पेंशन योजना शुरू की हुई है, जिसमें 1994 के बाद के पात्र पूर्व सरपंचों को अब 1000 प्रति माह की पेंशन मिल रही है। यह लाभ 2.5 वर्ष से अधिक कार्यकाल पूरा करने वाले सरपंचों को मिलता है, जो वृद्धावस्था पेंशन या अन्य कोई दूसरी पेंशन नहीं ले रहे हैं। इसके 1994 के बाद निर्वाचित और कम से कम 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सरपंच पात्र हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अन्य पेंशन नहीं ले रहे हैं। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

गांव झिमरेहड़ी के पूर्व सरपंच रामचंद्र ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए लाभकारी योजनाएं लागू की हुई हैं। जिनका संबंधित वर्गों को लाभ भी हो रहा है। सरपंचों के लिए वर्तमान में मानदेय लागू किया हुआ है और पूर्व होने पर पेंशन का प्रावधान करना काफी सराहनीय है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार है।

फुलकिया राजवंश की विरासत आज भी समाज को दे रही दिशा: नायब सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- नाभा हीरा महल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी में हुए शामिल

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के नाभा स्थित हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के लिए उनके परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका और अरदास की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि यह उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है, जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तित्वों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। हम महाराजा हीरा सिंह जी को याद करते हैं, जिनके शासन में प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण की नई मिसालें कायम हुईं। हम महाराजा रिपुदमन सिंह की अदम्य भावना को नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के समय में भी अपनी स्वतंत्र सोच और सिख पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस घराने के साथ जुड़ा वह आध्यात्मिक आशीर्वाद है, जो स्वयं दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। गुरु साहिब ने इस परिवार को ह्यतेरा घर, मेरा आसराह्ल का दिव्य वरदान दिया था। यह आशीर्वाद आज भी हीरा महल में गुरु साहिब के पवित्र अवशेषों की सेवा और संभाल के रूप में जीवित है।

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण भविष्य की नहीं वर्तमान की गंभीर चुनौतियां : प्रो. सोमनाथ सचदेवा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- उद्योग एवं आर्थिक जगत के सहयोग से पर्यावरणीय परिवर्तन संभव : प्रो. सोमनाथ सचदेवा
- केयू पर्यावरण अध्ययन संस्थान में उद्योग-संलग्न कौशल-आधारित पर्यावरण एवं सतत विकास पर साप्ताहिक कार्यशाला का शुभारंभ

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी अब भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की गंभीर चुनौतियां हैं, जिनका समाधान शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के प्रभावी सहयोग से ही संभव है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं सतत विकास पर ध्यान देना परमावश्यक है। यह उदगार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने सोमवार को केयू पर्यावरण अध्ययन संस्थान द्वारा उद्योग-संलग्न कौशल-आधारित पर्यावरण एवं सतत विकास विषय पर आयोजित साप्ताहिक कार्यशाला का बतौर मुख्यातिथि उद्घाटन करते हुए व्यक्त किए। इससे पहले कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा, प्रो. सीपी कौशिक, प्रो. एआर चौधरी, प्रो. जसबीर ढांडा, प्रो. परमेश कुमार सहित डॉ. भावना दहिया ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर नमन किया।

कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि पर्यावरण की समस्या भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की समस्या है। उन्होंने उच्च शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को अब केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें औद्योगिक स्तर पर सतत समाधान विकसित करने वाले केंद्र बनना होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग समस्याएँ लेकर आता है और अकादमिक जगत इसका समाधान प्रदान करता है। दोनों के सहयोग से ही बड़े स्तर पर पर्यावरणीय परिवर्तन संभव है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में ह्यजीरो डिस्चार्जह्ल मॉडल विकसित करने का आह्वान किया, जिससे शोध और नवाचार सीधे समाज और उद्योग को लाभ पहुँचा सकें। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता में निहित कर्म और कर्तव्य के संतुलन की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला विकसित भारत 2047 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है तथा नैतिक नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यावरण अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. परमेश कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ज्ञान और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना है। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला हरियाणा राज्य की संशोधित जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी फेज-2, 2021-2030) के अनुरूप कौशल-आधारित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

प्रो. सीपी कौशिक, प्रख्यात पर्यावरणविद् एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने बतौर संसाधन व्यक्ति एवं विशिष्ट अतिथि कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतत विकास को ध्यान में रखते हुए समाज को भी जोड़ना होगा ताकि आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

कार्यशाला की संयोजक डॉ. भावना दहिया ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था, कार्बन लेखांकन, ऊर्जा ऑडिट, नवीकरणीय ऊर्जा योजना, सतत कृषि तथा जल उपयोग दक्षता जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में 75 प्रतिभागी, जिनमें स्नातकोत्तर छात्र एवं शोधार्थी शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। वहीं उद्योग-संपर्क, क्षेत्रीय अध्ययन और वास्तविक केस स्टडीज के माध्यम से प्रतिभागियों को पर्यावरण प्रबंधन, सततता ऑडिट, हरित उद्यमिता एवं नीति-निर्माण से जुड़े करियर हेतु तैयार किया जाएगा।

इस अवसर पर केयू छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. एआर चौधरी, डीन जीवन विज्ञान संकाय प्रो. जसबीर ढांडा डीन, प्रो. भगवान सिंह, प्रो. परमेश कुमार, प्रो. दीपक राय, प्रो. अनीता भटनागर, प्रो. सुमन ढांडा, प्रो. जितेंद्र शर्मा, प्रो. अनीता दुआ, प्रो. रीटा, प्रो. विवेक चावला, प्रो. नीरज कुमार, प्रो. प्रेम कुमार, डॉ. जितेंद्र खटकर, डॉ. सुरेंद्र जागलान, डॉ. हरदीप राय शर्मा, डॉ. संदीप गुप्ता, डॉ. पूजा, डॉ. दीप्ति, डॉ. मीनाक्षी सुहाग, डॉ. सरिता राणा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार, डॉ. जितेंद्र भारद्वाज डॉ. हर

संपादकीय

कूटनीति की जीत! ट्रंप की सरप्राइज डील से भारत-अमेरिका फिर करीब

फरवरी 2026 की शुरूआत में भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित व्यापारिक समझौते (इंडिया-यू एस ट्रेड डील 2026) का ऐलान हुआ है, जिसने पिछले लगभग एक साल से जारी व्यापारिक तनाव और द्विपक्षीय अनिश्चितता के दौर को एक नई दिशा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा और सम्मान का भाव दिखाई दे रहा है, जो वैश्विक आर्थिक एवं कूटनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। अमेरिका ने भारत से जारी कई महीनों की व्यापारिक बातचीत और तनावपूर्ण चर्चा के बाद अचानक घोषणा की कि वह भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए उच्च टैरिफ को घटा रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों ने कुछ नीतिगत प्रतिबद्धताएं भी साझा की हैं, जिससे यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भावना का पुनर्निर्माण भी माना जा रहा है। इस नए समझौते के अनुसार, अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर लगभग 18% कर दिया है, जिसमें पहले 25% 'रेसिप्रोकल टैरिफ' और 25% 'पैनल्टी टैरिफ' शामिल थे। टैरिफ में यह कटौती भारतीय निर्यातकों के लिए राहत का बड़ा संदेश है, क्योंकि इससे 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती आएगी। हकीकत में अमेरिका ने निर्यात पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क में भी कटौती कर दी है, जिससे भारत की निर्यात क्षमता और बाजार पहुंच दोनों बेहतर हो सकती हैं। इस घोषणा के तुरंत बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी और रिलिफ रैली देखने को मिली। निफ्टी 50 सूचकांक में लगभग 3% तक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भारतीय रुपये ने भी डॉलर के मुकाबले उत्थान दिखाया, जो कई वर्षों में एक बड़ी एक-दिवसीय मजबूत स्थिति थी। डील के मुताबिक, भारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पाद (तेल), उन्नत तकनीक, रक्षा उपकरण, विमान और फार्मास्युटिकल्स जैसे सामानों का आयात बढ़ाने का संकेत दे रहा है, जबकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं को निर्यात में बढ़ावा देगा और अधिक बाजार पहुंच प्रदान करेगा। पिछले वर्ष भारत-अमेरिका के रिश्तों पर व्यापारिक तनाव ने भारी प्रभाव डाला था, विशेषकर जब अमेरिका ने उच्च टैरिफ और व्यापार दबाव जैसे उपाय उठाए थे, जिससे बातचीत और रणनीतिक साझेदारी बीच दरार नजर आई थी। अब यह समझौता केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे राजनीतिक संवाद और कूटनीतिक समझ का प्रतीक भी बताया जा रहा है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने 'सबसे अच्छे मित्र' के रूप में वर्णित किया है और दोनों देशों के बीच संवाद को जारी रखने की इच्छा जताई है। यह डील ऐसे समय में आई है जब भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ भी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक व्यापार मंच पर अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। भारत-अमेरिका का द्विपक्षीय संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और इंडो-पेसीफिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है। व्यापारिक रिश्तों का यह नया अध्याय इन सहयोगों को और मजबूती देगा। विशेषज्ञों की राय में यह डील विश्वसनीयता और विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल भारत के नियार्तों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश सहयोग को भी बढ़ावा देगा। भारत में ट्रेड डील पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। सत्तारूढ़ दल ने इसे ऐतिहासिक और आर्थिक सफलता बताया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की गई है और इसे 'विकसित भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है। वहीं विपक्षी दलों ने आलोचना की है और कहा है कि भारत ने अपनी नीति स्वतंत्रता को कुछ सीमा तक खो दिया है। कुछ आलोचक यह तर्क देते हैं कि भारत को अपनी कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों में और संतुलित नीति अपनानी चाहिए थी, जबकि कुछ ने 'ट्रंप-निर्भरता' का आरोप भी लगाया है। हालांकि व्यापार डील के घोषणा के बाद बाजार संतुलन में सुधार आया है, कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर फिलहाल कोई तत्काल बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि सेक्टर के हितों की रक्षा के साथ ही बाजार की स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। वहीं उद्योग समूहों ने डील को 'ट्रिपल बोनस' तक कहा है, क्योंकि इससे एम एस एम ई, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इस समझौते को सिर्फ एक तुरंत लाभ देने वाला सौदा मानना गलत होगा। यह दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का पहला चरण माना जा रहा है, जिसमें दोनों देश तकनीकी साझेदारी, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं को और मजबूत कर सकते हैं। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि अगला कदम एक अधिक व्यापक एफ टी ए की दिशा में हो सकता है, जिसमें सेवा व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, और निवेश पर विशेष समझौते शामिल होंगे। फरवरी 2026 की यह सरप्राइज ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच एक नए अध्याय की शुरूआत है। यह कदम न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि राजनयिक साझेदारी, साझा विकास और वैश्विक रणनीतिक समझौते को भी मजबूती से आगे बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच यह सहयोग स्थिर, दीर्घकालिक और पारस्परिक लाभकारी साझेदारी का प्रतीक बन सकता है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति पर भी पड़ेगा।

कैंसर मौन महामारी, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

लोगों को कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को ह्यविश्व कैंसर दिवसह्न मनाया जाता है। दरअसल, आज भी लगभग सभी लोगों के लिए कैंसर ऐसा शब्द है, जिसे अपने किसी परिजन के लिए डॉक्टर के मुंह से सुनते ही परिवार के तमाम सदस्यों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसे में परिजनों को परिवार के उस अभिन्न अंग को सदा के लिए खो देने का डर सताने लगता है। बढ़ते प्रदूषण तथा पोषक खानपान के अभाव में यह बीमारी महामारी के रूप में तेजी से फैल रही है। भारत में तो कैंसर के करीब दो तिहाई मामलों का बहुत देर से पता चलता है और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हमारे देश में पिछले बीस वर्षों के दौरान कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है और कैंसर से मौतों का आंकड़ा साल-दर-साल निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष कैंसर पीड़ित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व तक कैंसर को लाइलाज रोग माना जाता था लेकिन कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में क्रांतिकारी खोजें हुई हैं। जिसका नतीजा है कि अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो उसका उपचार किया जाना काफी हद तक संभव हो जाता है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है किन्तु अगर इसका सही समय पर पता लग जाए तो लाइलाज मानी जाने वाली इस बीमारी का उपचार अब संभव है। यही वजह है कि देश में कैंसर के मामलों को कम करने के लिए कैंसर तथा उसके कारणों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे इस बीमारी, इसके लक्षणों और इसके भयावह खतरे के प्रति जागरूक रहें।

कैंसर से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत तरीका यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जिसके चलते जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान हो सके और शुरूआती चरण में ही इसका इलाज संभव हो। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि जागरूकता के जरिये इस बीमारी को शुरूआती दौर में ही पहचान लेना बेहद जरूरी माना गया है क्योंकि ऐसे मरीजों के इलाज के बाद उनके स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जीने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। हालांकि देश में कैंसर के इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर हम इस बीमारी पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे इस बीमारी का इलाज महंगा होना सबसे बड़ी समस्या है। वैसे देश में जांच सुविधाओं का अभाव भी कैंसर के इलाज में बड़ी बाधा है, जो बहुत से मामलों में इस बीमारी के देर से पता चलने का एक अहम कारण होता है।

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ह्यकैंसरह्न आखिर है क्या? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमला करना शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अपने आप तेजी से विकसित और विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के समूह की इस अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता हैं। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है और कैंसर की यह स्थिति बहुत घातक हो जाती है।

दुनिया भर में कैंसर से लड़ने और इसे हराने के लिए निरन्तर चिकित्सीय खोजें हो रही हैं और इन प्रयासों के चलते ही अब कैंसर का शुरूआती चरणों में तो सफल इलाज संभव भी है। अगर शरीर में कैंसर होने के कारणों की बात की जाए तो इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं, उनमें मोटापा, शारीरिक सक्रियता का अभाव, व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, पौष्टिक आहार की कमी इत्यादि इन कारणों में शामिल हो सकते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कैंसर के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते किन्तु किसी अन्य बीमारी के इलाज के दौरान कोई जांच कराते वक्त अचानक पता चलता है कि मरीज को कैंसर है लेकिन फिर भी कई ऐसे लक्षण हैं, जिनके जरिये अधिकांश व्यक्ति कैंसर की शुरूआती स्टेज में ही पहचान कर सकते हैं।

कैंसर के लक्षणों में कुछ प्रमुख हैं- वजन का घटते जाना, शरीर में रक्त की कमी, निरन्तर बुखार बने रहना, शारीरिक थकान व कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी होना, दौरे पड़ना, आवाज में बदलाव, सांस लेने में दिक्कत, खांसी के दौरान खून आना, लंबे समय तक कफ रहना और कफ के साथ म्यूकस आना, कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, पेशाब और शौच के समय खून आना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन होना, माहवारी के दौरान अधिक स्राव होना इत्यादि।

कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, बायोलॉजिकल थैरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि के जरिये कैंसर का इलाज होता है किन्तु यह प्रायः इतना महंगा होता है कि एक गरीब व्यक्ति इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जरूरत इस बात की महसूस की जाती रही है कि कैंसर के सभी मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में, सरकार ऐसे मरीजों के इलाज में यथासंभव आर्थिक सहयोग करे क्योंकि जिस तेजी से देश में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे कैंसर मरीजों के इलाज की कल्पना बेमानी होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कैंसर को लेकर समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं जाएं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

मिट्टी की मयार्दा और जल की तपस्या से सजेगा 'हरित भविष्य'

भारतीय कृषि की गाथा आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दशकों पहले हमने खाद्यान्न की कमी वाले देश से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों और निर्यातकों की कतार में अपनी जगह बनाई। यह हमारी मेहनत और बेहतर बीजों, सिंचाई के विस्तार व रासायनिक उर्वरकों का ही परिणाम था। लेकिन आज जब मैं अपने गांव जखनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को छूता हूं, तो विशेषज्ञ एक गंभीर चेतावनी देते सुनाई देते हैं। वे कहते हैं कि जिस रासायनिक बैसाखी के दम पर हमने तरक्की की, उसने हमारी मिट्टी और पाताल के पानी को गहरा जख्म दिया है।

'साइलेंट वेल्थ' पर अदृश्य संकट

मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, बल्कि देश की 'साइलेंट वेल्थ' (मौन संपदा है, जो हमारी पूरी खाद्यन्न व्यवस्था की नींव है। लेकिन यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने इस संपदा को खोखला कर दिया है। आज हमारी मिट्टी में सिर्फ मुख्य पोषक तत्वों की ही नहीं, बल्कि सल्फर, जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों की भी भारी कमी हो गई है। नतीजा हमारे सामने है—मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है और खेतों की पैदावार थम सी गई है।

हमें अब '4R' के मंत्र को जीवन में उतारना होगाः सही स्त्रोत (Right Source), सही खुराक (Right Dose), सही समय (Right Time) और सही स्थान (Right Place)। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि मिट्टी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है ताकि पोषक तत्वों की बबार्दी न हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे।

उमाशंकर पांडेय

जखनी का अनुभवः हर खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़

मेरी जीवन यात्रा सूखे से जूझते बुंदेलखंड के जखनी गांव से शुरू हुई। साल 2005 में जब कोई सरकारी सहायता नहीं थी।बारिश के साथ बहती मिट्टी को खेत में रोकने के लिए कोई योजना भी नहीं थी। तब हमने सामुदायिक एकजुटता से परंपरागत जल संरक्षण 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' का अभियान शुरू किया। हमारा लक्ष्य सीधा था—बारिश की हर बूंद को खेत में रोकना और धरती की कोख(एक्वीफर)को फिर से भरना।

आज गर्व होता है कि नीति आयोग ने इस 'जखनी मॉडल' को सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से जल संरक्षण के लिए देशभर के सरपंचों को पत्र लिखा। जिस बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट जैसे जिलों में कभी गर्मियों में रेलगाड़ी से पानी आता था, वहां मेड़बंदी के कारण भू-जल स्तर में 1.34 मीटर तक का सुधार देखा गया है।लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है—यदि हम जल तो बचा लें, पर उर्वरकों और रसायनों के जहर से मिट्टी को न बचा पाए, तो यह सारी मेहनत बेकार जाएगी। जल संरक्षण के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती का संगम ही किसानों के लिए 'सोने पर सुहागा' साबित होगा।

एकीकृत पोषणः परंपरा और तकनीक का मेल

भविष्य की कृषि का आधार एकीकृत पोषण प्रबंधन (INM) है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम उर्वरकों को पूरी तरह त्याग दें, बल्कि उन्हें जैविक खाद, बायो-फर्टिलाइजर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित करें। सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। फर्मेंटेड जैविक खाद (FOM) और मोलासेस से निकलने वाले पोटाश (PDM) को अब उर्वरक सब्सिडी के दायरे में लाया गया है, ताकि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल सुधारा जा सके।

तकनीक भी अब किसान के दरवाजे पर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) अब महज एक कागज नहीं, बल्कि किसान का गाइड बन रहा है। इसे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (ड्ढ्ढळ) से जोड़ने की योजना है, जिससे हर खेत को उसकी जरूरत के हिसाब से 'पर्सनलाइज्ड' सलाह मिल सकेगी। गांवों में बन रहे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs) अब खेती के 'वन-स्टॉप हब' बन रहे हैं, जहां खाद से लेकर विशेषज्ञ सलाह तक सब एक छत के नीचे उपलब्ध है।

नैनो क्रांति और नीतिगत सुधार

भारत आज नैनो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नैनो यूरिया और लिक्विड बायो-फर्टिलाइजर जैसे उत्पाद न केवल बबार्दी रोकते हैं, बल्कि पैदावार भी बढ़ाते हैं। 'पीएम-प्रणाम' (PM-PRANAM) जैसी योजनाएं राज्यों को रासायनिक खादों का मोह छोड़ने और वैकल्पिक पोषक तत्वों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। साथ ही, कृषि में ड्रोन का प्रवेश 'प्रिसिजन फार्मिंग' यानी सटीक खेती के सपने को सच कर रहा है।

हालांकि, चुनौतियां अभी शेष हैं। यूरिया पर अत्यधिक सब्सिडी के कारण संतुलन अभी भी बिगड़ा हुआ है। हमें ऑर्गेनी-मिनरल फर्टिलाइजर (OMFs) के लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा चाहिए, ताकि खनिज और जैविक तत्वों का दोहरा लाभ खेतों तक पहुंच सके।

एक लचीला भविष्य

जैसे-जैसे भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा, सरकार, उद्योग व खेती करने वाले लोगों के बीच तालमेल बहुत जरूरी होगा। 4R के सिद्धांत को रसायनिक खादों के लिए अपनाने, खेती में आधुनिक तकनीक के विस्तार से बदलाव लाए जा सकते आज मिट्टी की सेहत को प्राथमिकता देकर, भारत का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2026 की देहरी पर खड़े होकर जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो उसका रास्ता हमारे खेतों की मेड़ों से होकर ही जाता है।

(लेखकपद्मश्री से सम्मानित, जलयोद्धाहै।)

शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव का बजट

डॉ. अवधेश कुमार यादव (हि.स)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के संघीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1,39,289.48 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है, जो विकसित भारत-2047 की मजबूत नींव रखने वाला कदम माना जा रहा है। यह राशि कुल बजट व्यय का लगभग 2.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 8.27 प्रतिशत अधिक है तथा शिक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हालांकि, यह धनराशि एनईपी-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य (शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय) से काफी कम है लेकिन वृद्धि मुद्रास्फीति से ऊपर होने के कारण एनईपी के क्रियान्वयन, विशेषकर अनुसंधान, नवाचार, स्किलिंग तथा शिक्षा-रोजगार संबंध स्थापित करने के क्षेत्रों में गति प्रदान करेगी।

इस कुल आवंटन को शिक्षा मंत्रालय के दो प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। पहला- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 83,562.26 करोड़ (6.35 प्रतिशत की वृद्धि) और दूसरा- उच्च शिक्षा विभाग को 55,727.22 करोड़ (11.28 प्रतिशत की वृद्धि)। यह वृद्धि एनईपी के मूल सिद्धांतों- पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य तथा जवाबदेही को सशक्त बनाती है, जहां शिक्षा को बहु-विषयी, लचीली, कौशल-आधारित और समावेशी बनाने पर बल दिया गया है।

स्कूल शिक्षा में अब तक का सर्वोच्च आवंटन एनईपी के प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक की एकीकृत शिक्षा को मजबूत करता है। समग्र शिक्षा अभियान को 42,100 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक निरंतर शिक्षा, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा डिजिटल क्लास रूम पर केंद्रित है। पीएम पोषण योजना को 12,750 करोड़ मिले हैं, जो 11 करोड़ से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उपस्थिति बढ़ाती है और कुपोषण घटाती है, जो एनईपी के समग्र विकास लक्ष्य से संरेखित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को 10,129 करोड़ तथा नवोदय विद्यालय समिति को 6,025 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हैं।

नवाचार को स्कूल स्तर पर एकीकृत करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स को 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 500 करोड़ से उल्लेखनीय छह गुना वृद्धि है। ये लैब्स छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करती हैं तथा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) आधारित प्रोजेक्ट्स पर कार्य करती हैं, जिससे ड्रॉपआउट दर घटेगी और विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। एनईपी के डिजिटल एवं क्रिएटिव शिक्षा फोकस को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई के सहयोग से 15,000 माध्यमिक स्कूलों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। यह 'ऑरेंज इकोनॉमी' को मजबूत करेगा तथा छात्रों को प्रारंभिक स्तर से अनुसंधान-आधारित क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में शामिल करेगा।

उच्च शिक्षा में एनईपी का बहु-विषयी तथा अनुसंधान-उन्मुख दृष्टिकोण प्रमुख है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 17,440 करोड़ तथा यूजीसी को 3,709 करोड़ प्राप्त हुए हैं। आईआईटी, एनआईटी तथा आईआईएम जैसे संस्थानों के लिए बढ़ा फंड एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर केंद्रित है, जिसमें एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 250 करोड़ तथा एआई इन एजुकेशन पहल के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। यह उभरती तकनीकों के एकीकरण को मजबूत करेगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप को 10,000 स्कॉलर्स तक विस्तारित किया गया है, जो युवा शोधकताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पीएम रिसर्च चेयर योजना के लिए 200 करोड़ तथा पीएम वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना को 2,200 करोड़ मिले हैं, जो शोध पत्रों तथा जर्नल्स तक केंद्रीकृत पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा वैश्विक स्तर के अनुसंधान को समर्थन देगी।

एनईपी में अनुसंधान एवं विकास पर जीडीपी का कम से कम 1 प्रतिशत व्यय तथा एनआरएफ (राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) के माध्यम से मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इस बजट में उच्च शिक्षा में अनुसंधान आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि से यह लक्ष्य निकट आता दिखता है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स की स्थापना (औद्योगिक गलियारों के निकट विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थान, स्किल सेंटर तथा आवासीय सुविधाओं के साथ) इंडस्ट्री-एकेडमिया लिंकेज को मजबूत करेगी, जहां संयुक्त प्रोजेक्ट्स जैसे एआई, बायोटेक्नोलॉजी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्य होगा। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना (कैपिटल सपोर्ट से), एसटीईएम में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाएगी, जहां वर्तमान दर अपेक्षाकृत कम है तथा एनईपी की लैंगिक समानता तथा अनुसंधान में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाएगी।

नए संस्थानों में तीन नए एनआईपीईआर (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च), पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अपग्रेड एनईपी के बहु-विषयी तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। एनआईपीईआर फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर फोकस करेंगे, जो बायोफार्मा तथा ड्रग डिस्कवरी में भारत को वैश्विक नेता बनाने की दिशा में सहायक होंगे। 'एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज' की हाई-पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी गठित होगी, जो शिक्षा को सेवाओं क्षेत्र (10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी लक्ष्य) तथा उभरती स्किल्स से जोड़ेगी तथा एआई के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

अन्य क्षेत्रों में 100,000 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जोड़ना, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वेटरनरी शिक्षा के लिए सब्सिडी तथा खेलो इंडिया मिशन के तहत स्पोर्ट्स साइंस एनईपी के स्वास्थ्य, पर्यटन तथा खेल शिक्षा को मजबूत करेंगे, जहां अनुसंधान जैसे स्पोर्ट्स साइंस में बायोमैकेनिक्स तथा पोषण पर फोकस होगा। एम्स, नई दिल्ली को 5,500.92 करोड़ तथा एनआईएमएचएएनएस-2 की स्थापना मेन्टल हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देगी। यह बजट शिक्षा व्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदलने वाला है क्योंकि यह एनईपी के विभिन्न स्तंभों- अनुसंधान एकीकरण, समावेशिता, कौशल विकास तथा रोजगार-उन्मुखीकरण को एक साथ मजबूत करता है।

यह बजट अनुसंधान एकीकरण, समावेशिता, कौशल विकास तथा रोजगार-उन्मुखीकरण के माध्यम से एनईपी के स्तंभों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान पर फोकस (एनआरएफ, पीएम रिसर्च चेयर, वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन), एआई तथा क्रिएटिव स्किल्स (एवीजीसी लैब्स) तथा इंडस्ट्री-एकेडमिया लिंकेज (यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, स्टैंडिंग कमिटी) भविष्योन्मुखी हैं। यदि क्रियान्वयन मजबूत हो, फंड का उपयोग समयबद्ध व प्रभावी हो तथा राज्य स्तर पर समन्वय बढ़े तो यह शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

(लेखक, राजकीय महाविद्यालय, कुल्लू में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय के सहायक प्रोफेसर हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विधि, प्रशासन या सलाहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास फलदायी रह सकता है। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी आपको नई पहचान दिलाएगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतना जरूरी है। गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुँचा सकता है। सरकारी या कागजी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें। आपसी समझदारी से पारिवारिक या सामाजिक विवाद सुलझा पाएंगे। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः आपकी मिलनसार छवि लोगों को प्रभावित करेगी। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ेगी। हर परिस्थिति में संतुलित प्रदर्शन आपको आगे बढ़ाएगा। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आयात-निर्यात या बाहरी संपर्क से जुड़े व्यापार में लाभ संभव है। काम के प्रति उत्साह बना रहेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखें। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। दोपहर बाद परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल होंगी। रिश्तेदारों या मित्रों का आगमन संभव है। सलाह लेकर निर्णय करना फायदेमंद रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः परिवार में मतभेद उभर सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें, खासकर विलासिता की वस्तुओं पर। गर्दन या कंधे में दर्द परेशान कर सकता है। दिखावे से दूर रहें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः अविवाहितों के विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है। व्यवसाय की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देंगे। योग, व्यायाम और ध्यान लाभकारी रहेंगे। रुके कार्य दोबारा शुरू करने में सफलता मिलेगी। उदार व्यवहार से सम्मान बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः किसी को उधार देने से पहले परिवार से सलाह लें। मेहनत का परिणाम अपेक्षा से कम मिल सकता है। घर की मरम्मत या साज-सज्जा की योजना बनेगी। कटु विचारों से छवि प्रभावित हो सकती है। पैसों के मामले में सतर्क रहें। *(सिटी दर्पण)*

धनुः आज के दिन व्यापार में नए प्रयोग कर सकते हैं। काम का दबाव धीरे कम होगा। आज के दिन बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार को समय देना आवश्यक है। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आज के दिन काम को लेकर आलोचना झेलनी पड़ सकती है। व्यवहार में नम्रता रखें, खासकर विपरीत लिंग के साथ। दांपत्य जीवन में हल्की तकरार संभव है। दोपहर बाद सिरदर्द हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें। *(सिटी दर्पण)*

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से हिंदुजा ग्रुप ने पंजाब में निवेश में गहरी रुचि दिखाई

ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक, पंजाब में निवेश की असीम संभावनाएं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
मुंबई

पंजाब को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश में और तेजी आई है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज विश्व प्रसिद्ध कंपनी हिंदुजा ग्रुप के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद कंपनी ने राज्य में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पंजाब को एक स्थिर, भविष्य के लिए तैयार और व्यवसाय-अनुकूल स्थान के रूप में पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र, नीतिगत सुधारों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को उजागर किया, जिसके कारण मार्च 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इलेक्ट्रिक गतिशीलता से लेकर डिजिटल सेवाओं तक के क्षेत्रों के विस्तार का स्पष्ट रोडमैप तैयार करने में मदद मिली है।

बैठक के दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, निवेश के दृष्टिकोण से पंजाब देश का सबसे पसंदीदा राज्य है क्योंकि यहां बुनियादी ढांचे की बेहतर सुविधाएं, अतिरिक्त बिजली, कुशल मानव संसाधन, शानदार सड़क, रेल और हवाई संपर्क, बेहतर दूरसंचार नेटवर्क और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन, वित्तीय और डिजिटल सेवाएं, डिजिटल तबदीली और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक प्रभाव, औद्योगिक और रियल एस्टेट सहयोग, रणनीतिक प्राप्तियां और निवेश जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अथाह संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, पंजाब के पास लचीलापन, उद्यमी मानसिकता और समृद्ध विरासत है और हिंदुजा ग्रुप इसका लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को भारत का अन्नदाता होने का सौभाग्य प्राप्त है और देश के अनाज भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां पंजाब ने परंपरागत रूप से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं राज्य का औद्योगिक क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू

रहा है। उन्होंने कहा, आज पंजाब एक औद्योगिक पावरहाउस है, जो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के औद्योगिक विकास ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है और दुनिया भर के निवेशक राज्य की क्षमताओं को मान्यता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 5.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने की संभावना है। राज्य औद्योगिक विकास और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।

विश्वस्तरीय निगमों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डैनोन जैसी कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में व्यवसायों के विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए उद्योग-अनुकूल माहौल का लाभ उठा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की वैश्विक पहुंच जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों द्वारा राज्य में निवेश की रुचि से स्पष्ट होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की विकास गाथा अभी शुरूआती दौर में है। भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब अब न केवल भारतीय निवेशकों के लिए बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थान बन गया है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में, राज्य सरकार ने जापान और कोरिया गणराज्य में उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां की हैं, जिससे पंजाब की वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, इन गतिविधियों ने उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और खेल विज्ञान में सहयोग के लिए नए रास्ते खोले हैं।

रोड शो के पहले दिन, पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, कारगिल इंडिया, हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड, वारी ग्रुप, पार्क्सन पैकेजिंग और विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल सहित प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय एक-से-एक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की।

चर्चा के दौरान पंजाब में फास्टट्रैक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली, समयबद्ध मंजूरियाँ, कारोबार करने का सरल ढांचा, नीति स्थिरता, कुशल मानव शक्ति और मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना को उजागर किया गया।

इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री की मेजबानी हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक पी. हिंदुजा ने की। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने कॉइन्स ऑफ कुनिंदस (पंजाब क्षेत्र) शीर्षक वाली एक पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया, जो पंजाब की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ इसके प्रगतिशील आर्थिक दृष्टिकोण को दशार्ती है।

पहले दिन का समापन एक पंजाब रोड शो सत्र के साथ हुआ, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, एक्सेंचर, यूपीएल, टायनोर, विस्लिंग वुड्स, ग्रोथकैप वेंचर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई जैसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ उद्योग नेताओं की जोरदार भागीदारी देखने को मिली। उद्योग प्रतिनिधियों ने पंजाब की औद्योगिक संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए और राज्य द्वारा प्रदान किए गए निवेशक-अनुकूल शासन वातावरण तथा जवाबदेह संस्थागत सहायता की सराहना की।

उद्योग भागीदारों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में निवेश करने का यह सही समय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और सेवाओं के आधार के रूप में उभरने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो न केवल घरेलू बाजारों बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आपूर्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों से पंजाब से कामकाज का स्तर बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और नवाचार, उत्पादकता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आान किया।

मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़े उद्यमों की ओर बढ़ने, विनिर्माण और सेवाओं को मजबूत करने तथा निरंतर सुधारों, आधारभूत ढांचे के विकास और सक्रिय निवेशक सुविधा के माध्यम से पंजाब को उत्तरी भारत में पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

नंगल-कीरतपुर साहिब सड़क को चार-मार्गी बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा: हरजोत बैंस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब

पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब से विधायक श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज नंगल-कीरतपुर साहिब सड़क को चार-मार्गी बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने का ऐलान किया, जिससे इस प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। लोगों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बताते हुए श्री बैंस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि भूमि प्राप्ति की प्रक्रिया अगले दो महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी, जिसके बाद टेंडरिंग और जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा।

एक वीडियो संदेश में, श्री बैंस ने बताया कि जुलाई 2022 में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के साथ प्रोजेक्ट का शुरूआती कार्य शुरू हुआ था। उन्होंने इस सड़क खासकर नंगल-गंगूवाल टोटे को तुरंत अपग्रेड करने की आवश्यकता की लगातार वकालत की थी, जहां सालों से हादसे हो रहे थे और कई कीमती जानें जा रही थीं। उन्होंने कहा, यह सड़क सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है क्योंकि यह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों और माता बगलामुखी, बाबा बालक नाथ तथा माता चिंतपूर्णी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आने-जाने की सुविधा प्रदान करती है। सर्वेक्षण डेटा और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के निरंतर फॉलो-अप के आधार पर, इस सड़क को चार-मार्गी बनाने की सख्त जरूरत सामने आई।कैबिनेट मंत्री ने प्रोजेक्ट की प्रगति का श्रेय सभी स्तरों पर अधिकारियों के निरंतर समन्वय को दिया। उन्होंने कहा, यह एक जनता की मांग थी। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टरों तक, इस मामले की लगातार पैरवी की गई। एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, जमीनी स्तर पर विकास करना हमेशा मेरी प्राथमिकता रहा है।

इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, यह सड़क हमारे क्षेत्र के भविष्य के लिए मेरी दृष्टि को दशार्ती है। गुरु साहिब और लोगों के आशीर्वाद से हम इसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित बनाएंगे और सुरक्षा, संपर्क तथा समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत करेंगे।

गुरमीत खुड्डियां द्वारा उद्योगों को अथाह संभावनाओं वाले पंजाब के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए निमंत्रण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा वैज्ञानिक ढंग से फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान हो, मिट्टी की सेहत में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

वे आज यहां ए.एस.ए.आर. द्वारा कैनोपी के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।स. खुड्डियां ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही पराली जलाने की समस्या को पंजाब ने लाभकारी आर्थिक और पर्यावरण-अनुकूल अवसरों में बदलने में सफल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब द्वारा फसल अवशेषों के सुचारू प्रबंधन के प्रयासों से प्रभावी और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2025 के खरीफ सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में ऐसी घटनाओं की संख्या 10,909 थी, जो अब घटकर 5,114 रह गई है।

कृषि मंत्री ने सब्सिडी वाली फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी, प्रोत्साहन और पराली के उपयोग के लिए व्यावहारिक विकल्पों की उपलब्धता को इस सफलता का कारण बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि राज्य द्वारा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए आधुनिक इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों का उपयोग करके हर साल उत्पन्न होने वाली 20 मिलियन टन पराली में से 80 प्रतिशत से अधिक पराली का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

रेलवे मंडल ने जनवरी माह में टिकट चैकिंग द्वारा 2.52 करोड़ रूपए जुमार्ना वसूला

जैतो। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल द्वारा मंगलवार को जारी प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि फिरोजपुर मंडल के टिकट चैकिंग दल द्वारा ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से यात्रा कर रहे रेलयात्रियों की इस प्रवृति पर रोक लगाने हेतु ट्रेनों में सतत टिकट चैकिंग किया जा रहा है। मंडल के टिकट चैकिंग स्टाफ एवं मुख्य टिकट निरीक्षकों द्वारा जनवरी, 2026 के दौरान ट्रेनों में टिकट चेकिंग के दौरान कुल 39,215 यात्री बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करते हुए पाए गए एवं उनसे जुमार्ने के तौर पर लगभग 02.52 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया। फिरोजपुर मंडल द्वारा जनवरी, 2026 के दौरान टिकट चैकिंग द्वारा अर्जित राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।मंडल के रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा बनाए रखने तथा आम जनता को स्टेशनों पर गंदगी फैलाने से रोकने एवं उनको साफ-सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए मंडल के मुख्य स्टेशनों पर नियमित जाँच की जाती है। इसके फलस्वरूप, जनवरी माह में 428 यात्रियों को स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने के कारण (एंटी लिटरिंग एक्ट) उनसे 72 हजार रुपए से अधिक वसूल किये गए। मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने बताया कि फिरोजपुर मंडल में टिकट चैकिंग अभियान जारी रहेंगे। टिकट चैकिंग का मुख्य उद्देश्य रेलवे टिकटों की बिक्री में सुधार और बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों से जुमार्ना वसूल करना ताकि वे भविष्य में उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि यह उपलब्धि मंडल के टिकट चैकिंग स्टाफ की सक्रियता, समर्पण और सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अनियमित यात्रा और गंदगी फैलाने से रोकने के लिए रेलयात्रियों को नियमों के पालन हेतु लगातार अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है।

फरीदकोट जिले में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी: एसएसपी डॉ.प्रज्ञा जैन

जैतो। श्री गौरव यादव आईपीएस, डीजीपी पंजाब के निदेर्शों के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान के तहत, डॉ.प्रज्ञा जैन आईपीएस सीनियर कप्तान पुलिस फरीदकोट के नेतृत्व में, फरीदकोट पुलिस लगातार नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। जिसके तहत, पुलिस प्रशासन जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और इलाकों में नशीली दवाओं के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका समर्थन करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जिले के मुख्य अधिकारी, पुलिस स्टेशन और चौकी प्रभारी और गांवों और शहरों में ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) और वार्ड रक्षा समितियों के सदस्यों के साथ बैठकें की गईं। जिसमें सामाजिक नेताओं और जनता ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान, पुलिस अधिकारियों ने नशीली दवाओं के मानसिक और शारीरिक प्रभावों के बारे में गहन जानकारी दी, साथ ही उपस्थित लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान देने की अपील की। इस दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्राम रक्षा समितियों (श्उ्ढ) और वार्ड रक्षा समितियों के सदस्यों के साथ बैठकें कीं और उनसे नशा विरोधी अभियान के लिए सुझाव लिए। इस अभियान का उद्देश्य गांव स्तर पर नशीली दवाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. प्रज्ञा जैन एसएसपी फरीदकोट ने कहा कि फरीदकोट पुलिस नशे को खत्म करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत नशा विरोधी अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। जिसके तहत, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और बुरे लोगों से पेशेवर तरीके से निपटा जा रहा है। इसके साथ ही, एसएसपी फरीदकोट ने लोगों से नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की और किसी भी नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधि के बारे में नशा विरोधी हेल्पलाइन 97791-00200 पर जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होंने दोहराया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में गिरने से बचाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार नशा मुक्त राज्य के सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह लड़ाई केवल आम भावना और सामूहिक भागीदारी से ही जीती जा सकती है।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रेंट कुलेक्टर और चपरासी रंगे हाथों काबू

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम के दौरान, पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में तैनात रेंट कुलेक्टर मोहम्मद यासीन और पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में तैनात ठेके आधारित चपरासी मोहम्मद तालीम को 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आज यहां यह खुलासा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आरोपियों को बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता, जो एक किसान है, ने 2018 से 2021 की अवधि के लिए तहसील बलाचौर के गांव भड्डी में स्थित पंजाब वक्फ बोर्ड की 10 कनाल जमीन लीज पर ली थी। वर्ष 2021 में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद शिकायतकर्ता ने लीज के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए आरोपी मोहम्मद यासीन से पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में संपर्क किया। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आरोपी मोहम्मद यासीन ने लीज के नवीनीकरण के लिए फाइल तैयार करने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थता जताई तो फिर रिश्वत की मांग को घटाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। इसमें से आरोपी मोहम्मद यासीन ने मौके पर ही 2,000 रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए थे और शिकायतकर्ता को बाकी 18,000 रुपये बाद में देने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की एसबीएस नगर टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

हरजोत सिंह बैंस द्वारा श्री दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश

चंडीगढ़। शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब से विधायक श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाब के मुख्य सचिव को 180 एकड़ सरकारी जमीन पर संचालित श्री दसमेश अकादमी, श्री आनंदपुर साहिब संबंधी आईं गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट करवाने के आदेश दिए हैं। श्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दसमेश अकादमी में वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन में गड़बड़ियों और बुनियादी ढांचे से संबंधित कमियों के आरोपों की गहन जांच के लिए कहा है। शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), रूपनगर द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद सामने आईं महत्वपूर्ण कमियों के बाद जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ट्रस्ट के फंडों में कथित गबन, संस्था की संपत्ति के दुरुपयोग

और बुनियादी ढांचे से संबंधित कमियों का कारण बनने वाली आपराधिक लापरवाही की जांच की जाएगी। श्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब पुलिस को अकादमी के प्रिंसिपल की कथित जाली पीएच.डी. डिग्री की जांच करने और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ को रोकने के लिए सभी संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आदेश देते हुए 30 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान, जो ट्रस्ट के एक्स-ऑफिशो चेयरमैन हैं, के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए पेश किए जाएंगे। श्री हरजोत बैंस ने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे शैक्षणिक संस्थानों की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम इस मामले की तह तक जाएंगे और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों की भलाई और सार्वजनिक संसाधनों की कीमत पर निजी जागीर के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे।

पंजाब सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़: 111 मामले रोके गए: डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य से बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है।यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से अब तक पंजाब में बाल विवाह के 111 मामले समय रहते रोके गए हैं, जो मान सरकार की बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।

उन्होंने जिला-वार विवरण साझा करते हुए बताया कि अमृतसर में 5, बरनाला 1, बठिंडा 9, फतेहगढ़ साहिब 4, फिरोजपुर 4, फाजिल्का 18, फरीदकोट 3, गुरदासपुर 8, होशियारपुर 1, जालंधर 2, लुधियाना 3, कपूरथला 5, मानसा 8, मोगा 12, मुक्तसर साहिब 5, पटियाला 4, पठानकोट 2, रोपड़ 1, संगरूर 1, मोहाली 4, शहीद भगत सिंह नगर 5 और तरनतारन में 6 बाल विवाह के मामले रोके गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती के साथ-साथ संवेदनशीलता के साथ भी कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने आगे बताया कि बाल विवाह रोकने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी (सीएमपीओज) नियुक्त किए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं

बाल विकास विभाग के सीडीपीओज और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हैं।

इस संदर्भ में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि हर रोका गया बाल विवाह एक बच्ची को अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपनी पहचान बनाने और आत्म-निर्भर जीवन की ओर बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि मान सरकार का यह सपना है कि पंजाब का हर बच्चा डर से मुक्त, सुरक्षित और सम्मान से भरा बचपन जीए, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर दृढ़ता से काम करती रहेगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जन-सहयोग के बिना कोई भी मुहिम सफल नहीं हो सकती। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को अपने आसपास बाल विवाह संबंधी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित किया जाए या अपने नजदीकी बाल विवाह निवारण अधिकारी से संपर्क किया जाए।

एस.जी.एस.टी. वसूली दर में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि, राष्ट्रीय औसत को भी किया पार

पंजाब एस.जी.एस.टी. विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भारत सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 दर को तर्कसंगत बनाने के कारण राजस्व संबंधी चुनौतियों के बावजूद, पंजाब ने जनवरी 2026 के दौरान जीएसटी जुटाने में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो बेहतर अनुपालन, केंद्रित लागूकरन और निरंतर आर्थिक गतिविधियों को दशार्ता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2026 के दौरान राज्य में कुल 2452.66 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया है, जबकि शुद्ध जीएसटी वसूली के मामले में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत की दर से वर्ष-दर-वर्ष 315 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

श्री चीमा ने कहा कि यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी 2.0 दर में कटौती के कारण पंजाब को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए। इस नुकसान के बावजूद, राज्य ने न केवल राजस्व पर पड़े प्रभाव की भरपाई की, बल्कि निरंतर प्रशासनिक और लागूकरण प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय रुझान से भी अधिक विकास दर हासिल की।

अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (जनवरी 2026 तक), शुद्ध जीएसटी वसूली की दर में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वसूला गया कुल जीएसटी 19,415 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये हो गया है।इसी अवधि के दौरान कुल जीएसटी वसूली की दर में भी 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पंजाब में कर

आधार के लचीलेपन को दशार्ता है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली के मामले में भी असाधारण प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिसमें 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह विकास दर इस महीने के दौरान भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यह दर राष्ट्रीय औसत लगभग 6 प्रतिशत से काफी अधिक है, जिससे पंजाब पूरे भारत में अग्रणी बनकर उभरा है।

मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा करदाताओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केवल जनवरी 2026 के दौरान ही 129 करोड़ रुपये के एसजीएसटी रिफंड जारी किए गए, जबकि महीने में कुल रिफंड किया गया जीएसटी लगभग 300 करोड़ रुपये है। समय पर और नियमित रूप से रिफंड सुनिश्चित करना तथा व्यापक स्तर पर राजस्व जुटाना एक परिपक्व, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल कर प्रशासन को दशार्ता है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों के भी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (एसआईपीयू) ने जनवरी 2026 के दौरान सड़कों पर जांच, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से आईटीसी चोरी को रोककर और जाली बिलिंग के रुझान को रोककर 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है।इसके साथ ही, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवर्तन संबंधी कुल वसूली 1,000 करोड़ रुपये के करीब है, जो अब तक की सबसे अधिक वसूली है, जो स्पष्ट रूप से कर चोरी के खिलाफ तेज और डेटा-आधारित कार्रवाई को दशार्ती है।

मंत्री ने बताया कि जीएसटी 2.0 से संबंधित चुनौतियों के अलावा, पिछले तीन महीनों के दौरान केंद्र द्वारा आईजीएसटी निपटान से लगभग 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती के कारण पंजाब को और वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा है। इस सबके बावजूद पंजाब ने मजबूती के साथ विकास की ओर बढ़त बनाए रखी है, जो इसके बेहतर जीएसटी प्रबंधन और पालना संबंधी इकोसिस्टम को दशार्

अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा- भारत के साथ किया व्यापार समझौता, तत्काल टैरिफ कम होगा

पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदन बंद करने, वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने का वादा किया: ट्रंप

- ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि समझौते के तहत भारत अमेरिकी उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदने पर सहमत

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता (ट्रेड डील) हो गया है। वह तत्काल एक-दूसरे के सामान पर टैरिफ कम करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस से तेल खरीदन बंद करने, अमेरिका और संभवतः, वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने का वादा किया है। ट्रंप ने सोमवार को भारतीय नेता के साथ बातचीत के बाद ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझौते के तहत अमेरिकी उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदने पर सहमत हुए हैं।

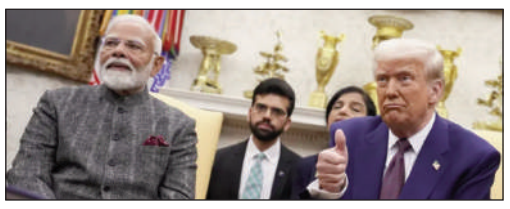

ट्रंप की घोषणा

सीएनबीसी की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी घोषणा का प्रसारण किया गया है। वह इस प्रकार है- आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक ताकतवर और सम्मानित नेता हैं। हमने कई बातों पर बात की, जिसमें ट्रेड और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है। वह रूसी तेल खरीद बंद करने और यूनाइटेड स्टेट्स और शायद वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदने के लिए सहमत हुए। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत असर से हम यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। वे भी इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को घटाकर शून्य कर देंगे। प्रधानमंत्री ने 46 लाख करोड़ रुपये (500 अरब डॉलर) से ज्यादा की अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा, बहुत अधिक स्तर पर बाय अमेरिकन करने का भी वादा किया।

व्हाइट हाउस ने तत्काल टिप्पणी नहीं की

ट्रंप की घोषणा में कहा गया है कि फोन कॉल पर हुए समझौते बिना किसी देरी के लागू होंगे। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन डील का लिखित स्वरूप अभी सामने नहीं आया है और यह साफ नहीं है कि इस पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं। व्हाइट हाउस और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने इस पर अधिक जानकारी के लिए किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों और कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना कोई भी बाध्यकारी व्यापार समझौता कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने दोबारा पद संभालने के बाद कई बार किया है। ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि कांग्रेस ने ऐसे सौदे करने के लिए कार्यकारी शाखा को अधिकार दे दिया है। रोजर्स एंड ब्राउन कस्टम ब्रोकर्स की ऑपरेशंस डायरेक्टर लोरी मुलिंस ने बताया कि उनका समूह ट्रंप की सार्वजनिक व्यापार घोषणाओं पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देगा। मुलिंस ने कहा, यह तभी आधिकारिक होता है जब फेडरल रजिस्टर नोटिस तारीखों, समय और लागू टैरिफ कोड के साथ पोस्ट किया जाता है। ट्रंप और मोदी प्रशासन के बीच व्यापार वार्ता पिछले साल कई मुद्दों पर अटक गई थी। इसकी वजह नई दिल्ली का रूसी तेल पर लगातार निर्भर होना शामिल था। अगस्त में ट्रंप ने तेल खरीद के जवाब में भारत पर 25 फीसद टैरिफ लगाया था। यह उस 25 फीसद पारस्परिक लेवी के अलावा था जो उसी महीने की शुरूआत में देश के अमेरिका जाने वाले सामानों पर लागू हुआ था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप

ट्रंप ने लिखा, भारत भी इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य कर देगा। भारतीय नेता मोदी ने सोमवार को बाद में एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी टैरिफ में कमी की पुष्टि की। मोदी ने लिखा, खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18 फीसद कर दिया जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

बलोच लिबरेशन आर्मी ने नुश्की शहर से सेना को खदेड़ा, मजीद ब्रिगेड के फिदायीन दंपति की मौत

एजेंसी (हि.स.)
क्वेटा (बलोचिस्तान)

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में सेना को विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि नुश्की शहर से सेना को खदेड़ दिया है। शहर में अभी भी उसका नियंत्रण है। साथ ही पिछले दिनों के घमासान में बीएलए के मजीद ब्रिगेड के फिदायीन दंपति की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने कहा कि बीएलए से सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी। द बलोचिस्तान पोस्ट की मंगलवार को प्रसारित रिपोर्ट के अनुसार, नुश्की अभी भी बीएलए के नियंत्रण में है। जमीनी संचार सेवाएं बाधित हैं। लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना के हवाई हमलों के बावजूद बलोच लड़ाके नुश्की शहर पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। खारान के पास बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के दो जमीनी हमलों को विफल कर दिया। इसके बाद सेना को पीछे हटना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने दूसरे और तीसरे दिन दर्जनों ड्रोन हमले किए। बावजूद इसके सेना अभी तक नुश्की

फोटोः हि.स.

शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार सुबह अन्य शहरों की तरह समन्वित अभियानों के माध्यम से नुश्की पर भी नियंत्रण कर लिया। इसके बाद सशस्त्र लड़ाको ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ पाकिस्तान के आईएसआई मुख्यालय और सेना के कई शिविरों पर हमला किया। पिछले तीन दिन से आईएसआई मुख्यालय में तैनात कई अधिकारी और कर्मचारी बीएलए के हमलों का शिकार हुए हैं। तीन दिन बीत जाने के बावजूद सेना अपने कर्मियों को बचाने और उन्हें सहायता प्रदान करने में विफल रही है। नुश्की शहर में नाकाबंदी के कारण अन्य शहरों के निवासी अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंतित हैं। कैडेट कॉलेज में दर्जनों छात्र फंसे हुए हैं। इस बीच बीएलए के आधिकारिक चैनल हकाल पर मजीद ब्रिगेड में शामिल पति -पत्नी का फोटो और विवरण प्रसारित किया गया है। इस दंपति ने पाकिस्तान की सेना के शिविर पर हमले के दौरान जान गंवा दी। यास्मा बलूच उर्फ जरीना और वसीम बलोच उर्फ जरबर (पति-पत्नी) जमरान के रहने वाले थे। यास्मा बलोच का जन्म 14 फरवरी, 1997 को अल-अंदुर बुलाइदा में हुआ था और वह 2022 में मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी। वसीम बलोच का जन्म 27 अप्रैल, 1992 को कलहादर जमरान में हुआ था। वह 2014 में बीएलए में शामिल हुए और 2022 में मस्जिद ब्रिगेड का हिस्सा बने। इस लड़ाई पर रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि बलोचिस्तान में महिलाओं और बच्चों पर हमला करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि पंजाब में भी बड़ी संख्या में बलोच रहते हैं। बलोचिस्तान में मेडिकल कॉलेजों सहित बड़ी संख्या में शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान हैं। बलोचिस्तान में तेल सहित विभिन्न सामानों की रोजाना तस्करी हो रही है।

स्पेसएक्स और एक्सएआई का विलय, मस्क ने कहा- यह अध्याय नहीं, अभियान की अगली किताब

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और प्रसिद्ध टेक उद्यमी एलन मस्क की दो कंपनियों स्पेसएक्स और एक्सएआई का विलय हो गया। स्पेसएक्स ने सोमवार को घोषणा की कि उसने एक्सएआई को खरीद लिया है। इस विलय के बाद यह दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट इकाई बन गई है। स्पेसएक्स की वेबसाइट पर एक बयान में मस्क ने कहा, यह सिर्फ अगला अध्याय नहीं, बल्कि स्पेसएक्स और एक्सएआई के अभियान की अगली किताब है। सीएनएन की रिपोर्ट में इस विलय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस विलय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए एक्सएआई को जरूरी नकद पूंजी और साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण (स्पेस एक्सप्लोरेशन) के भविष्य में तकनीक (टेक्नोलॉजी) के महत्व के संकेत के

फोटोः हि.स.

तौर पर देखा जा सकता है। यह कदम यह भी दिखाता है कि मस्क जैसी कंपनियों जैसे टेक दिग्गज एआई में ऊंची छलांग लगाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। मस्क ने लिखा, एआई में मौजूदा तरक्की बड़े जमीनी डेटा सेंटर पर निर्भर है। इसके लिए बहुत अधिक बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है। इसलिए इस क्षेत्र को ऐसी जगह ले जाना है जहां बहुत अधिक बिजली और जगह हो। स्पेसएक्स ने शुक्रवार को फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से 10 लाख सैटेलाइट का एक समूह ऑर्बिट में लॉन्च करने की इजाजत मांगी। अनुरोध में कहा गया है कि इसका मकसद सोलर-पावर्ड डेटा सेंटर का एक नेटवर्क देना है ताकि एआई की वजह से डेटा की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। मस्क ने अनुमान जताया है कि दो से तीन साल में एआई कंप्यूट जेनरेट करने का सबसे सस्ता तरीका अंतरिक्ष में होगा।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

नई दिल्ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील का असर घरेलू बाजार में साफ-साफ नजर आ रहा है। शेयर बाजार ने आज तूफानी तेजी के साथ कारोबार की शुरूआत की। शुरूआती कारोबार में ही निफ्टी जोरदार छलांग लगा कर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। हालांकि मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट भी आई। इसके बावजूद ये दोनों सूचकांक जोरदार बढ़त बनाए हुए हैं। सुबह 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 2.51 प्रतिशत और निफ्टी 2.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। मंगलवार सुबह 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल, इंटरग्लोब एवियशन और बजाज फाइनेंस के शेयर 9.91 प्रतिशत से लेकर 4.95 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, नेस्ले, ओएनजीसी और आईटीसी के शेयर 1.07 प्रतिशत से लेकर 0.54 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,786 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 2,452 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

सराफा बाजार की कमजोरी जारी सोना-चांदी की घटी कीमत

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

घरेलू सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में गिरावट का रुख लगातार जारी है। सोना आज 6,800 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 7,410 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 19 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक की दर्ज की गई है। सोने की कीमत में कमजोरी आने के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,53,160 रुपये से लेकर 1,53,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,40,390 रुपये से लेकर 1,40,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सराफा बाजार में आज 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,53,310 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22

फोटोः हि.स.

कैरेट सोने की कीमत 1,40,540 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,53,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,440 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,40,390 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

पीएनबी शाखा में 6.5 करोड़ का गोल्ड लोन घोटाला, मैनेजर सहित तीन पर मामला दर्ज

झुंझुनू। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में संचालित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये के गोल्ड लोन घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक में गिरवी रखे गए असली सोने के आभूषणों के स्थान पर नकली आभूषण रखकर चार किलो से अधिक सोना गायब कर दिया गया। मामले में बैंक मैनेजर सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फजीर्वाड़े का प्रकरण दर्ज किया गया है। घोटाले के खुलासे के बाद शाखा के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार वर्तमान शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार सिहाग की ओर से पूर्व शाखा प्रबंधक अमित कुमार जांगिड़, उप प्रबंधक अनंतप्रकाश चौधरी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट संतोष कुमार सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शिकायत में बताया गया कि गोल्ड लोन प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए स्वर्ण आभूषणों के पैकेट्स से छेड़छाड़ कर असली आभूषणों की जगह नकली आभूषण रख दिए गए। बैंक रिकॉर्ड के अनुसार गोल्ड लोन से जुड़े करीब 450 पैकेट स्ट्रांग रूम स्थित गोल्ड सेफ में रखे गए थे। जांच में लगभग 250 पैकेट्स से छेड़छाड़ की आशंका सामने आई है। फिलहाल 73 पैकेट्स में नकली सोने के आभूषण पाए गए हैं। इन पैकेट्स से कुल 4 किलो 198 ग्राम नकली सोने के जेवरात बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत साढ़े छह करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। शेष पैकेट्स की जांच जारी है। पुलिस ने तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार जांगिड़ निवासी सीथल (गुढ़ागौड़जी), बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट संतोष कुमार सैनी निवासी बाजीवाली ढाणी झाझड़ (नवलगढ़) और उप प्रबंधक अनंतप्रकाश चौधरी निवासी मुकुंदगढ़ (नवलगढ़) के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैंक प्रबंधन की आंतरिक जांच के दौरान शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। वहीं 22 जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों को स्ट्रांग रूम स्थित गोल्ड सेफ में रखे स्वर्ण पैकेट्स से छेड़छाड़ करते हुए पाया गया।

हत्या प्रकरण में चौकी प्रभारी निलंबित प्राथमिक जांच के आदेश

देहरादून। देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र में हाल ही में युवती की हत्या मामले में लापरवाही पाए जाने के बाद एसएसपी देहरादून ने चौकी प्रभारी खुड़बुड़ा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पूरे प्रकरण की प्राथमिक जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में चौकी प्रभारी की संभावित लापरवाही पर प्रकाश डाला। इस आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने उप निरीक्षक प्रद्युमन नेगी ने तत्काल प्रभाव से खुड़बुड़ा को निलंबित कर दिया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराध की जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से हो। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि सभी पुलिस स्टाफ को अपने दायित्वों का पालन पूरी गंभीरता से करना होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रकरण की जांच जारी है और पुलिस ने जनता से अपील की है कि मामले से संबंधित किसी भी जानकारी को वे तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएं। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति का हिस्सा मानी जा रही है।

मालदह में मादक तस्करी का भंडाफोड़, करीब 17 किलो ब्राउन शुगर जब्त

मालदह। मालदह जिले के इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत कुम्हारपुर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक तस्करी के एक बड़े गिरोह का पदार्फाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 16 किलो 998 ग्राम ब्राउन शुगर, आठ लाख 78 हजार 500 रुपये नकद, 20 किलो सोडियम कार्बोनेट, लगभग 25 किलो लाइम हाइड्रॉक्साइड और कुल 80 लीटर तरल पदार्थ से भरी चार सीलबंद पानी की बोतलें बरामद कीं। इसके अलावा नशीले पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली पंचिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, पुराने उपकरण और बर्तन भी जब्त किए गए। मंगलवार को पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। तलाशी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार अपराह्न सब-इंस्पेक्टर अभिषेक भट्टाचार्य को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुम्हारपुर स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जमा किए गए हैं, जिन्हें पैसों के बदले सप्लाई करने की तैयारी है। सूचना के आधार पर एसआई अभिषेक भट्टाचार्य अपनी टीम के साथ महिबुबा खातून के गैराज कक्ष में छापेमारी करने पहुंचे। छापेमारी के दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल के निवासी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान एक एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स मोबाइल फोन के साथ-साथ एक स्लाविया मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो वाहन, एक कर्व कार और दो आरसी बुक भी जब्त की गईं। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि बिहार से आए आरोपित कुम्हारपुर से ब्राउन शुगर एकत्र कर उसे बिहार के विभिन्न हिस्सों में बेचने और तस्करी करने का काम करते थे। इस नेटवर्क के जरिए लंबे समय से अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी), 25, 27(ए), 29 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 111/61(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

मामूली विवाद पर हल्द्वानी में चले लात-घूंसे

हल्द्वानी। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास सोमवार रात दो दुकानदारों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने एक दुकानदार और उसके कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी, घटना में दुकान संचालक का सिर फट गया। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों की मदद से दोनों घायलों को युवकों के चंगुल से निकाला और दूसरे स्थान पर ले गए। घटना के दौरान आक्रोशित युवक दुकान में तोड़फोड़ करने लगे, जिन्हें अन्य दुकानदारों ने मुश्किल से शांत कराया। लालकुआं कोतवाली पहुंचे दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। और देर रात तक कोतवाली में ही जमे रहे। एक पक्ष ने दूसरे पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप लगाए, वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताकर बेवजह मारपीट किए जाने की बात कही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लालकुआं कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ग्लोबल मार्केट से मजबूती के संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से आज पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करने के बाद बंद हुए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी आज बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। वहीं एशियाई बाजार में भी आज आमतौर पर तेजी का रुख बना हुआ है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,976.50 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 136.48 अंक यानी 0.58 प्रतिशत उछल कर 23,598.30 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 49,463.78 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार तेजी का माहौल बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 118.02 अंक यानी 1.14 प्रतिशत की मजबूती के साथ 10,341.56 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,181.17 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

प्रचंड की पार्टी ओली से कोई चुनावी तालमेल नहीं करेगी

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' ने कहा कि इस चुनाव में केपी शर्मा ओली के साथ कोई चुनावी तालमेल नहीं होगा। उन्होंने आज काठमांडू में पत्रकारों से कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से संवाद कर रहे हैं। ओली का नाम लेकर प्रचंड ने कहा कि उनके साथ चुनावी तालमेल की कोई संभावना नहीं है।

प्रचंड ने कहा, मैं यह बात पूरी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मेरी बातचीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के नेताओं से भी हो रही है और कांग्रेस के नेताओं से भी। कल शेरबहादुर देउवाजी से मुलाकात हुई। आज गगन थापा से भी बातचीत जारी है। केपी ओली से बातचीत करने का मतलब यह नहीं कि कोई सिद्धांत या पहचान खत्म हो जाती है। सभी से संवाद हो रहा है और होता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने सभी

फोटोः हि.स.

165 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कहीं भी कोई चुनावी तालमेल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा सभी से बातचीत करना मेरी विशेषता है। मैं सहज रूप से संवाद करता हूं। झापा में केपी ओली को समर्थन करने के सवाल पर प्रचंड ने कहा कि राजनीति में कुछ भी पूरी तरह असंभव नहीं होता, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। केपी ओली से कभी फोन पर, कभी प्रत्यक्ष मुलाकात में चर्चा होती रहती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, रवि लामिछाने समेत कई नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं।

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की निपाह वायरस से सतर्क रहने की अपील

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को निपाह वायरस को लेकर नागरिकों से घबराने के बजाय सतर्क और जिम्मेदार रहने की अपील की है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ देशों में निपाह वायरस के मामलों से वह अवगत है। इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि एहतियात के तौर पर महामारी विज्ञान एवं रोग नियंत्रण प्रभाग (ईडीसीडी) ने देशभर के स्वास्थ्य संस्थानों और संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया है तथा निपाह वायरस की जांच के लिए व्यवस्था की गई है। यह वायरस संक्रमित चमगादड़ों के मूत्र, मल या लार से दूषित फलों के सेवन के माध्यम से फैल सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से मानक स्वास्थ्य उपाय

फोटोः हि.स.

अपनाने का आग्रह किया है। इनमें फलों को अच्छी तरह धोकर सेवन करना, सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाना, उबला या सुरक्षित पानी पीना, पशुशालाओं और खेतों में स्वच्छता बनाए रखना, दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना, साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना शामिल है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, मतली, उल्टी या गंभीर मामलों में बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर संबंधित व्यक्ति को अलग रखा जाए और तुरंत सूचना दी जाए। संदिग्ध लक्षण महसूस होने पर नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें या स्वास्थ्य हॉटलाइन 1115 पर कॉल करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नेपाल में अब तक निपाह वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है और किसी भी संभावित जोखिम को न्यूनतम करने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण पूरी तरह तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार संस्थाओं के समन्वय में स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है तथा नागरिकों से अफवाहों से बचने और केवल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ईडी का कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई स्थानों पर छापा

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज सुबह पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक साथ बड़ी कार्रवाई की। कोलकाता, दुगार्पुर, आसनसोल, बर्धमान और दिल्ली सहित कुल नौ ठिकानों पर ईडी की टीमों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी कोयला तस्करी से अर्जित काले धन को हवाला के जरिए कहां और कैसे भेजा गया, इसी नेटवर्क की जांच के तहत की जा रही है। दुगार्पुर में ईडी ने कई जगहों पर एक साथ छापा मारा। सुबह करीब छह बजे दुगार्पुर के सेपको टाउनशिप में बालू कारोबारी प्रवीर दत्त के आवास पर ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा सिटी सेंटर इलाके के अंबेडकर सरणी स्थित एक मकान और पांडवेश्वर व कांकसा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के बाइपास के पास एक अन्य आवास पर भी तलाशी ली गई। यह सभी बालू कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच

फोटोः हि.स.

एजेंसी के अनुसार, ये कारोबारी अजय और दामोदर नदियों से बालू निकालकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करते थे। आरोप है कि वैध टेंडर के जरिए अधिकृत बालू घाटों से खनन के साथ-साथ कई स्थानों पर अवैध रूप से भी बालू निकाला जाता था। इसके अलावा, बालू के चालान में हेराफेरी और एक ही चालान का कई बार इस्तेमाल कर तस्करी करने के भी आरोप हैं। यह भी आरोप है कि बीरभूम जिले के बालू के चालान का इस्तेमाल कर पश्चिम बर्धमान जिले में बालू की अवैध आपूर्ति की जाती थी। ईडी को संदेह है कि इसी अवैध कारोबार के जरिए आरोपितों ने बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल, सभी ठिकानों पर तलाशी के अलावा दस्तावेजों की जांच चल रही है।

पर्यटन को बढ़ावा | **उत्तराखंड में पर्वतारोहण को नई उड़ान**

83 हिमालयी चोटियां अभियानों के लिए खुलीं

एजेंसी (हि.स.)
देहरादून

देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग

अफगानिस्तान पर जीत के साथ भारत छटी बार खिताब जीतने की दिशा में आगे बढ़ेगा

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत-अफगानिस्तान में भिड़त

एजेंसी (हि.स.)
हरारे

अब तक खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम बुधवार को यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरूआत करेगी।इस प्रतियोगिता के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। उसने पांच बार (2000, 2008, 2012, 2018, 2022) खिताब जीते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसने चार बार ट्रॉफी जीती है।

इस तरह से भारत रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने की दिशा में बुधवार को एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अपने सभी पांच मैच आसानी से

फोटोः हि.स.

जीते हैं, जिसमें सुपर सिक्स चरण में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर 58 रन की जीत भी शामिल है। भारतीय टीम हालांकि अफगानिस्तान को कम करके आंकने की गलती नहीं करेगी। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उसने अपने पांच मैचों में से चार जीते हैं। उसे एकमात्र हार श्रीलंका से मिली थी। लेकिन खिलाड़ियों की फॉर्म और खेल के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक पांच मैचों में दो अर्धशतकों की मदद से 199 रन बनाए हैं। बड़े-बड़े शॉट खेलने में माहिर सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (पांच मैचों में दो अर्धशतकों सहित 196 रन) भी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन टीम प्रबंधन चाहेगा कि वह अपने अर्धशतकों को शतकों में तब्दील करें। ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा (पांच मैचों में 172 रन) एक और भारतीय बल्लेबाज हैं जिन पर सभी की नजर रहेगी। उन्होंने ग्रुप चरण में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक (109 नाबाद) लगाया था। कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने पांच मैचों में अपनी ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी से छह विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 99 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 53 रन है। सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज की फॉर्म भी भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि दाएं हाथ का यह बल्लेबाज तीन पारियों में केवल 46 रन ही बना सका है। भारतीय गेंदबाजी की कमान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और आरएस अंबरीश के हाथ में है।

टीम इस प्रकार हैं

भारत अंडर-19: आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन सिंह।

अफगानिस्तान अंडर-19: महबूब खान (कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदजई, उस्मान सादात, उजैरुल्लाह नियाजई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातिर स्टानिकजई, नाजीफुल्लाह अमीरी, नूरिस्तानी उमरजई, रुहुल्लाह अरब, सलाम खान, वहीदुल्लाह जादरान, जैतुल्लाह शाहीन।

मैच दोपहर 1:00 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा।

टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले पैट कमिंस-मेरे पास समय ही कम पड़ गया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ पैट कमिंस ने खुलासा किया है कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का हिस्सा बनने के बेहद करीब थे, लेकिन रिकवरी में हुई मामूली देरी के कारण अंतिम 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना सके। पीठ की चोट से जूझ रहे कमिंस को टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बेन ड्वार्शिस ने रिप्लेस किया है। 7 फरवरी से शुरू हो रहे मेगा टूर्नामेंट से बाहर होने पर कमिंस ने कहा कि वह शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह फिट होने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचा था।

कमिंस ने आईसीसी के हवाले से कहा, यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, बस एक छोटी-सी परेशानी थी और सच कहूं तो समय ही कम पड़ गया। अब मैं कुछ हफ्तों तक आराम करूंगा और फिर आगे की योजना बनाऊंगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बताया कि एडिलेड टेस्ट के बाद मेडिकल टीम ने उनकी पीठ को पूरी तरह ठीक होने के लिए चार से आठ हफ्तों का समय देने

फोटोः हि.स.

की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, हमें पता था कि एडिलेड टेस्ट के बाद हड्डी को पूरी तरह स्थिर होने के लिए चार से आठ हफ्तों की जरूरत होगी, उसके बाद ही दोबारा वर्कलोड बढ़ाया जा सकता था। शुरूआत में लगा था कि चार हफ्ते काफी होंगे, क्योंकि मैं अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन फॉलो-अप स्कैन के बाद लगा कि इसे दो हफ्ते और चाहिए। कमिंस ने आगे कहा, इसके चलते समय-सारिणी बहुत टाइट हो गई और वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट होना मुश्किल हो गया। अब कमिंस को मार्च में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की उम्मीद है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका मुख्य लक्ष्य साल के दूसरे हिस्से में होने वाले अहम टेस्ट मुकाबलों के लिए पूरी तरह फिट रहना है। ऑस्ट्रेलिया के सामने आगे व्यस्त टेस्ट कार्यक्रम है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज, दक्षिण अफ्रीका का दौरा और फिर न्यूजीलैंड व भारत के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा होंगे। कमिंस ने कहा, आने वाले क्रिकेट को देखते हुए हमें लगा कि साल के पहले हिस्से में सतर्क रहना सही रहेगा। अगर अभी सावधानी नहीं बरती जाती और चोट दोबारा उभरती, तो मुश्किलें बढ़ सकती थीं। वर्ल्ड कप से बाहर रहने के बावजूद कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हालिया पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 कसीरीज में मिली हार टीम की वास्तविक क्षमता को नहीं दशार्ती।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान में हमारा प्रदर्शन बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन खिलाड़ी मजबूत बिग बैश सीजन से आ रहे हैं और कुछ खिलाड़ी चोट से उबरकर वर्ल्ड कप में लौट रहे हैं। टीम का मनोबल अच्छा है और सभी टूर्नामेंट शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टी-20 वर्ल्ड कप 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम ग्रुप स्टेज में आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान और सह-मेजबान श्रीलंका से मुकाबला करेगी।

भारत अगले साल एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग निशानेबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत अगले साल दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप (राइफल/पिस्टल) की मेजबानी करेगा, जिसमें 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए आठ कोटा स्थान दांव पर लगे होंगे। यह भारतीय निशानेबाजी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी क्योंकि वह पहले ही एक अन्य ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी हासिल कर चुका है। एशियाई प्रतियोगिता में ओलंपिक के लिए आठ स्थान अगले वर्ष 21 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में होने वाले विश्व कप (राइफल/पिस्टल/शॉटगन) में उपलब्ध 12 कोटा स्थानों के अतिरिक्त होंगे। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव को लिखे पत्र में इसकी पुष्टि की। एनआरएआई ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में होगा और इसकी तिथियों को जल्द ही अंतिम

फोटोः हि.स.

रूप दिया जाएगा। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ ने पत्र में कहा, हम भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को एशियाई राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी हासिल करने पर बधाई देते हैं, जहां लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए आठ कोटा स्थान वितरित किए जाएंगे। पत्र में कहा गया है, हमें पूरा विश्वास है कि आपके (एनआरएआई) नेतृत्व में चैंपियनशिप का आयोजन उच्चतम मानकों के अनुरूप होगा और यह एक सफल प्रतियोगिता साबित होगी। एनआरएआई के महासचिव पवनकुमार ने कहा, यह ऐतिहासिक अवसर होगा जबकि भारत दो ओलंपिक कोटा प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा और हमें इस पर बहुत गर्व है।

हमारा ध्यान पूरी तरह से टी-20 विश्व कप जीतने पर केंद्रित, सुरक्षा पर पूरा भरोसाः मार्श

लाहौर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने इन दोनों मसलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका पूरा ध्यान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने पर है। मार्श कल रात यहां मेजबान टीम के हाथों टी-20 श्रृंखला में 0-3 से मिली हार के बाद पाकिस्तान के मीडिया से रूबरू थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से टीम के प्रदर्शन के अलावा मैदान से बाहर चल रही गतिविधियों के बारे में भी सवाल पूछे गए जिनके कारण भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप को लेकर चचाओं का बाजार गर्म है। मार्श से जब 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार करने के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

इटली पहली बार टी-20 विश्व कप में छाप छोड़ने के लिए तैयार

बेंगलुरु। फुटबॉल के दीवाने इटली में क्रिकेट की शुरूआत 18वीं शताब्दी में हो गई थी लेकिन यह खेल हमेशा वहां हाशिये पर ही रहा लेकिन दो सदियों के बाद अब लगता है कि इस देश में क्रिकेट गुमनामी से बाहर निकल आएगा। वेन मैडसन की अगुवाई वाली इटली की टीम आगामी टी-20 विश्व कप में छाप छोड़ने के लिए तैयार है और यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। पिछले महीने आयरलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में चार विकेट से मिली जीत टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ इटली की पहली जीत थी। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस ऐतिहासिक जीत के सूत्रधारों में से एक सहायक कोच केविन ओब्रायन थे जो आयरलैंड के मशहूर पूर्व ऑलराउंडर हैं। इटली ने ओब्रायन के अलावा कनाडा के पूर्व बल्लेबाज जॉन डेविसन को मुख्य कोच के रूप में अपने सहयोगी स्टाफ में शामिल किया है। इंग्लैंड के लिए 25 वनडे और दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच तथा वारविकशर के लिए 209 प्रथम श्रेणी के मैच खेलने वाले डौगी ब्राउन टीम के दूसरे सहायक कोच हैं। इटली क्रिकेट महासंघ (आईसीएफ) की अध्यक्ष लोरिया हाज पाज ने कहा, हमारे सहयोगी स्टाफ के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है और वे जानते हैं कि विश्व कप में खेलने के लिए क्या जरूरी होता है। यह हमारे लिए वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे युवा खिलाड़ी उनसे इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताओं में दबाव झेलने के लिए काफी कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी टीम टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछले साल 11 जुलाई को आईसीसी के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करना इटली क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन वह इस सफलता पर संतुष्ट होकर बैठने को तैयार नहीं था। आईसीएफ ने पिछले साल नवंबर से खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए दुबई और श्रीलंका में शिविरों का आयोजन किया। डेविसन ने कहा, सबसे अहम बात यह स्वीकार करना था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इन शिविर से टीम को काफी फायदा हुआ क्योंकि यहां की परिस्थितियां भारतीय परिस्थितियों से काफी हद तक मिलती-जुलती थीं। इससे खिलाड़ियों को यह पता चला कि विश्व कप में उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। इससे उन्हें विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में भी मदद मिली। इटली की टीम को उम्मीद है कि वह ग्रुप सी के अपने पहले दो मैचों में स्कॉटलैंड (जिसने बांग्लादेश की जगह ली है) और नेपाल के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करेगी।

बेंजेमा अल हिलाल से जुड़े, रोनाल्डो की उम्मीदों पर फेर सकते हैं पानी

रियाद। फ्रांस के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा सऊदी अरब के एक क्लब अल इत्तिहाद को छोड़कर दूसरे क्लब अल हिलाल से जुड़ गए हैं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खिताब जीतने की उम्मीदों के लिए बुरी खबर हो सकती है। पूर्व बैलोन डीओर विजेता बेंजेमा सऊदी प्रो लीग के अग्रणी क्लब अल हिलाल में शामिल हो गए हैं, जो रोनाल्डो के क्लब अल नासर से लीग तालिका में एक अंक आगे है। रोनाल्डो को 2022 में सऊदी अरब के क्लब से जुड़ने के बाद से अब भी अपने पहले लीग खिताब का इंतजार है। अल हिलाल उनके क्लब का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है जिसने पांच बार के चैंपियंस लीग विजेता बेंजेमा को टीम में शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रियाल मैड्रिड के पूर्व स्ट्राइकर बेंजेमा ने पिछले साल अल इत्तिहाद को लीग के खिताब के साथ-साथ किंग्स कप का चैंपियन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई थी।

डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज रॉटरडैम ओपन से हटे

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज इस साल एबीएन एमरो (रॉटरडैम) ओपन में अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे। टूर्नामेंट आयोजकों ने सोमवार को पुष्टि की कि विश्व नंबर एक अल्कराज एटीपी 500 स्तर के इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। स्पेन के स्टार खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कड़े अभियान के बाद कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है, जहां उन्होंने मेलबर्न में ऐतिहासिक खिताबी जीत दर्ज की थी। अल्कराज के इस फैसले के साथ ही रॉटरडैम आहोय में उनकी दोबारा मौजूदगी की संभावना समाप्त हो गई है। उन्होंने 2025 में इसी टूर्नामेंट में एलेक्स डी मिनौर को तीन सेटों में हराकर खिताब जीता था, जो उनके करियर का पहला इंडोर एटीपी खिताब भी था।

एबीएन एमरो ओपन के आयोजकों ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कार्लोस अल्कराज रॉटरडैम में

फोटोः हि.स.

अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान पिछले दो हफ्तों में काफी मेहनत के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें दोबारा खेलने से पहले और समय की जरूरत है। हम कार्लोस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अल्कराज का यह फैसला ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी ऐतिहासिक सफलता के तुरंत बाद आया है, जहां उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर पहली बार खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही 22 वर्षीय अल्कराज ओपन एरा में सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए।

दर्पण

विश्व कैंसर दिवस : जागरूकता ही सबसे अच्छा बचाव

कैंसर एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां सीमित स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता की कमी के कारण देर से निदान और उच्च मृत्यु दर होती है। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस कैंसर के गंभीर प्रभाव को पहचानने और प्रभावित लोगों के लिए शुरूआती पहचान, समय पर उपचार और सहायता के महत्व को पहचानने के लिए समर्पित दिन है। इस लेख में, हम कैंसर, रोकथाम रणनीतियों और उपचार में नवीनतम विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाएंगे, जिससे आपको बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि, जब कैंसर की बात आती है, तो जागरूकता वास्तव में सबसे अच्छा बचाव है।

विश्व कैंसर दिवस का इतिहास

विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में नई सहस्राब्दी के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में की गई थी। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। शिखर सम्मेलन का समापन पेरिस अगेंस्ट कैंसर के चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें अनुसंधान, रोकथाम और बेहतर रोगी देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तब से, विश्व कैंसर दिवस एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जो दुनिया भर के लोगों को जागरूकता बढ़ाने, कलंक को कम करने और कैंसर के खिलाफ कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए एकजुट करता है।

कैंसर के बारे में मुख्य तथ्य

कैंसर दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो हर साल लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसके पैमाने और महत्व को समझने के लिए यहां कुछ जरूरी तथ्य दिए गए हैं।

वैश्विक प्रभावः कैंसर दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है, जिससे हर साल 10 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं। (स्रोतः WHO)

बढ़ते मामलेः 2020 में, अनुमानित 19.3 मिलियन नए कैंसर के मामले थे, और 2020 की तुलना में 2025 में मामलों में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। (स्रोतः एनआईएच - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ)

आर्थिक बोझः कैंसर की वैश्विक आर्थिक लागत सालाना 1.16 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो स्थायी स्वास्थ्य देखभाल समाधानों की आवश्यकता को उजागर करता है। (एनआईएच - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ)

रोकथाम योग्य कारणः लगभग 30-50% कैंसर के मामलों को स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों और टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। (स्रोतः ठक्ष्ष - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ)

प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने से जीवन बचता हैः कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने से उपचार के परिणामों और जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय सुधार होता है।

सामान्य प्रकारः सबसे प्रचलित कैंसर में फेफड़े, स्तन, कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट, त्वचा (मेलेनोमा) और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर शामिल हैं। प्रत्येक के अपने अलग-अलग जोखिम कारक और रोकथाम के तरीके हैं।

प्रारंभिक पहचान में जागरूकता की भूमिका

कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब बात समय रहते पता लगाने की हो। कैंसर की शुरूआती अवस्था में पहचान करने से उपचार के परिणाम और बचने की दर में काफी सुधार हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि जागरूकता बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है।

लक्षणों को जल्दी पहचानना

कई कैंसर में सूक्ष्म लक्षण दिखते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। जन जागरूकता अभियान लोगों को चेतावनी के संकेतों को समझने में मदद करते हैं, जैसे- अस्पष्टीकृत गांठ या सूजन, लगातार खांसी या स्वर बैठना, असामान्य रक्तस्राव या स्राव, तिल या त्वचा की बनावट में परिवर्तन, लंबे समय तक थकान या बिना किसी कारण के वजन कम होना, लोगों को इन लक्षणों के बारे में शिक्षित करने से उन्हें शीघ्र ही चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जीवनशैली में बदलाव को प्रोत्साहित करना

जागरूकता अभियान जीवनशैली से जुड़े उन कारकों पर प्रकाश डालते हैं जो कैंसर के जोखिम में योगदान करते हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन, खराब आहार, शारीरिक निष्क्रियता और यूवी जोखिम। अभियान लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे- धूम्रपान छोड़ना, संतुलित आहार बनाए रखना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, सनस्क्रीन का उपयोग करना और टैनिंग बेड से बचना।

नियमित जांच को बढ़ावा देना

कैंसर के लक्षण दिखने से पहले ही उसका पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग जरूरी है। जागरूकता पहल नियमित जांचों के महत्व पर जोर देती है, जैसे- स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राम, गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के लिए पैप स्मीयर, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए परीक्षण, मेलेनोमा के लिए त्वचा की जाँच, इन जांचों से कैंसर को उसके प्रारंभिक, अधिक उपचार योग्य चरणों में पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे उसके बढ़ने का जोखिम कम हो जाता है।

विश्व कैंसर दिवस का मिशन

विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य इस जीवन-परिवर्तनकारी बीमारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों, संगठनों और सरकारों को एकजुट करके कैंसर के वैश्विक बोझ को कम करना है। यह वार्षिक उत्सव एक मंच के रूप में कार्य करता है।

जागरूकता बढ़ाएँः कैंसर के जोखिम, लक्षणों और शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करें।

रोकथाम को बढ़ावा देंः स्वस्थ जीवनशैली में बदलाव को प्रोत्साहित करें जो कैंसर के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं, जैसे धूम्रपान छोड़ना, संतुलित आहार बनाए रखना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना।

देखभाल तक पहुंच में सुधारः कैंसर की जांच, उपचार और उपशामक देखभाल तक समान पहुंच की वकालत करें, विशेष रूप से वंचित समुदायों में।

अनुसंधान का समर्थन करेंः उपचार को आगे बढ़ाने और इलाज खोजने में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालें।

सहयोग को बढ़ावा देनाः प्रभावशाली, समुदाय-संचालित पहल बनाने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को एक साथ लाना।

कैंसर अनुसंधान और उपचार में हालिया प्रगति

कैंसर अनुसंधान और उपचार में प्रगति ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे रोगियों के लिए बेहतर परिणाम और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद जगी है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई को बदलने वाले नवीनतम नवाचारों का विस्तृत विवरण यहां दिया गया है।

1. **इम्यूनोथेरेपीः प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग-** इम्यूनोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ाकर कैंसर के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। **सीएआर-टी सेल थेरेपीः** यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण रोगी की टी-कोशिकाओं को विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए संशोधित करता है। इसने कुछ रक्त कैंसर के उपचार में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है। **प्रतिरक्षा जांच बिंदु अवरोधकः** ये दवाएं, पेम्ब्रोलिजुमाब की तरह, उन प्रोटीनों को अवरुद्ध करती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर पर हमला करने से रोकती हैं, जिससे वे मेलेनोमा और फेफड़ों के कैंसर जैसे कैंसर के लिए प्रभावी होती हैं।
2. **व्यक्तिगत चिकित्साः अनुकूलित उपचार-** आनुवंशिक अनुसंधान में प्रगति के कारण रोगी की आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर उपचार को अनुकूलित करना संभव हो गया है। **लक्षित चिकित्साः** इमैटिनिब और ट्रैस्टुजुमाब जैसी दवाएं कैंसर कोशिकाओं में विशिष्ट आनुवंशिक उत्परिवर्तन पर हमला करने के लिए तैयार की गई हैं, जबकि स्वस्थ ऊतकों को भी नहीं छोड़ा जाता है। **जीनोमिक परीक्षणः** विशिष्ट उत्परिवर्तनों की पहचान करने से डॉक्टरों को सबसे प्रभावी उपचारों का चयन करने में मदद मिलती है, जिससे उपचार में परीक्षण-और-त्रुटि दृष्टिकोण कम हो जाता है।
3. **लिक्विड बायोप्सीः एक गैर-आक्रामक सफलता-** तरल बायोप्सी कैंसर के निदान और निगरानी में परिवर्तन ला रही है। ये रक्त परीक्षण परिसंचारी ट्यूमर डीएनए (सीटीडीएनए) और अन्य बायोमार्करों का पता लगाते हैं, जिससे उपचार की प्रगति का शीघ्र पता लगाने और उस पर नजर रखने में मदद मिलती है। तरल बायोप्सी पारंपरिक बायोप्सी की तुलना में कम आक्रामक होती है और इससे प्रारंभिक अवस्था में ही कई कैंसरों का पता लगाया जा सकता है।
4. **विकिरण चिकित्सा में प्रगति-** विकिरण चिकित्सा अधिक सटीक होती जा रही है, जिससे दुष्प्रभाव कम हो रहे हैं और परिणाम बेहतर हो रहे हैं। **प्रोटॉन बीम थेरेपीः** विकिरण का यह उन्नत रूप ट्यूमर को सटीक रूप से लक्षित करता है, जबकि आसपास के स्वस्थ ऊतकों को बचाता है, जिससे यह बाल चिकित्सा और कठिन उपचार वाले कैंसरों के लिए आदर्श बन जाता है। **छवि-निर्देशित विकिरण चिकित्सा (आईजीआरटी):** वास्तविक समय इमेजिंग यह सुनिश्चित करती है कि विकिरण सटीक रूप से दिया जाए।
5. **mRNA वैक्सीनः कोविड-19 से कैंसर तक-** कोविड919 के लिए mRNA टीके की सफलता ने कैंसर के टीकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। कंपनियां mRNA आधारित कैंसर टीके विकसित कर रही हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानना और नष्ट करना सिखाते हैं। मेलेनोमा और अन्य कैंसरों को लक्षित करने वाले टीकों के प्रारंभिक परीक्षण आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं।
6. **कैंसर देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कैंसर अनुसंधान और उपचार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। **प्रारंभिक पहचानः** एआई एल्गोरिदम उच्च सटीकता के साथ इमेजिंग स्कैन का विश्लेषण करते हैं, जिससे फेफड़े और स्तन कैंसर जैसे कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने में मदद मिलती है। **औषधि खोजः** एआई आणविक संरचनाओं और नैदानिक परीक्षणों के विशाल डेटासेट का विश्लेषण करके संभावित औषधि उम्मीदवारों - प्रभावी औषधि बनने की क्षमता वाले अणुओं या यौगिकों - की पहचान में तेजी लाता है।
7. **प्रशामक देखभाल में प्रगति-** प्रशामक देखभाल का ध्यान कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। नई दर्द प्रबंधन तकनीकें और एक्यूपंक्चर तथा माइंडफुलनेस जैसी एकीकृत चिकित्साएं रोगियों को लक्षणों और दुष्प्रभावों से निपटने में मदद कर रही हैं। कीमोथेरेपी से उत्पन्न न्यूरोपैथी को कम करने तथा उन्नत कैंसर के रोगियों में भूख में सुधार लाने जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान प्रगति पर है।
8. **कैंसर की रोकथाम की रणनीतियाँ-** रोकथाम कैंसर अनुसंधान का प्रमुख केन्द्र बनता जा रहा है। **टीकेः** निवारक टीकों पर अनुसंधान जारी है, जिनमें एपस्टीन-बार और हेपेटाइटिस सी जैसे वायरसों को लक्षित करने वाले टीके भी शामिल हैं। **रसायन-निवारणः** अध्ययन कैंसर के विकास को रोकने के लिए दवाओं या प्राकृतिक यौगिकों के उपयोग की खोज कर रहे हैं, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम के लिए एस्पिरिन।
9. **सर्जिकल तकनीकों में प्रगति-** न्यूनतम आक्रामक सर्जरी और रोबोट-सहायता प्राप्त तकनीकें सटीकता को बढ़ा रही हैं और रिकवरी का समय कम कर रही हैं। **रोबोटिक सर्जरीः** दा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसी प्रणालियां सर्जनों को जटिल प्रक्रियाओं को अद्वितीय सटीकता के साथ करने में सक्षम बनाती हैं। **इंट्राऑपरेटिव इमेजिंगः** सर्जरी के दौरान वास्तविक समय इमेजिंग कैंसरग्रस्त ऊतक को पूरी तरह से हटाने को सुनिश्चित करती है।
10. **अनुसंधान में वैश्विक सहयोग-** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कैंसर अनुसंधान में प्रगति तेज हो रही है। अमेरिका में कैंसर मूनशॉट जैसी पहल तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईएआरसी जैसे वैश्विक संगठन कैंसर से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संसाधनों को एकत्रित कर रहे हैं। सहयोगात्मक परीक्षणों से विविध आबादी में उपचारों का तेजी से परीक्षण और सत्यापन संभव हो पाता है।

भारत में कैंसरः प्रमुख चुनौतियाँ और अवसर

भारत में कैंसर का बोझ बहुत ज्यादा है, जिसमें सबसे आम प्रकार स्तन

पंचकूला में क्षेत्रीय पीएमईजीपी खादी प्रदर्शनी का भव्य आयोजन

देश के 13 राज्यों से प्रीमियम खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की सहभागिता

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी), चंडीगढ़ द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्तर की पी.एम.ई.जी.पी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों–पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिहार से खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रीमियम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला एक ही मंच पर प्रस्तुत की जा रही है।

डॉ वी. सिवक कुमार राज्य निदेशक के.वी.आई.सी चंडीगढ़ ने बताया की यह प्रदर्शनी पारंपरिक शिल्पकला, सतत विकास और उद्यमिता की भावना को प्रदर्शित करती है तथा आगंतुकों को एक ही छत के नीचे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करती है।

उन्होंने बताया कि 85 से अधिक प्रचार-सह-विक्रय स्टॉलों के साथ यह प्रदर्शनी दशहरा ग्राउंड (शालीमार ग्राउंड), सेक्टर-5, पंचकूला में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का एक जीवंत और प्रामाणिक बाजार उपलब्ध कराती है।यह प्रदर्शनी 30 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है तथा जन-प्रतिक्रिया के आधार पर इसे अतिरिक्त दो दिनों के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है। प्रदर्शनी में खादी और पीएमईजीपी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है, जो पारंपरिक शिल्पकला की समृद्धता को आधुनिक उपयोगिता के साथ प्रस्तुत करती है।

प्रदर्शित प्रमुख उत्पादों की श्रेणियाँ

* वस्त्र एवं परिधानः हस्तकरघा सूती, रेशमी एवं पॉलीवस्त्र कपड़े, पॉली-ऊन फैब्रिक, कुर्तियां, बेडशीट, तकिया कवर, परदे तथा अन्य परिधान।

* जैकेट एवं वेस्टकोटः प्रिंटेड खादी सूती जैकेट, कानपुरी प्रिंटेड कुर्ते, रिवर्सिबल जैकेट, पॉलीवस्त्र बंदी/हाफ जैकेट एवं संबंधित परिधान।

* हर्बल एवं आयुर्वेदिक व्यक्तिगत देखभाल उत्पादः आयुर्वेदिक औषधियाँ, हर्बल चाय, कंडीशनर, साबुन, मालिश तेल, फेस वॉश, लोशन, लिप बाम, सनस्क्रीन, हेयर ऑयल, अगरबत्ती, धूप एवं अन्य प्राकृतिक उत्पाद।

* होम फर्निशिंग एवं उपयोगी वस्तुएँः तौलिए, कंबल, मेजपोश, कुशन कवर एवं सजावटी वस्तुएँ।

* खाद्य उत्पादः शहद, जैम, अचार एवं पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा तैयार अन्य मूल्य-संवर्धित खाद्य उत्पाद।

* एक्सेसरीजः ऊनी शॉल, गर्म स्टोल, दुपट्टे, पर्स तथा विभिन्न प्रकार के चमड़े के उत्पाद।

उन्होंने बताया की प्रदर्शनी अवधि के दौरान आगंतुकों के लाभ हेतु अगरबत्ती निर्माण मशीनों, पॉटरी निर्माण तथा देसी चरखा, बॉक्स चरखा और एनएमसी चरखा जैसी विभिन्न कताई तकनीकों के लाइव प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक विशेष खादी सेल्फी प्वाइंट भी स्थापित किया गया है, जहाँ खादी प्रेमी फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। 100 या उससे अधिक लाइक्स प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक सरप्राइज उपहार प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने बताया की मित्रों एवं परिवारों को अपने बच्चों सहित प्रदर्शनी में पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया गया है, जहाँ वे शीतकालीन संध्याओं का आनंद लेते हुए फूड स्टॉल्स पर गर्म नाश्ते का स्वाद ले सकते हैं। बच्चे पॉटरी निर्माण एवं चरखा कताई गतिविधियों में भाग लेकर इस भ्रमण को शैक्षणिक एवं मनोरंजक बना सकते हैं। आगंतुकों से अनुरोध किया गया है की वे अपने परिवार सहित शीघ्र प्रदर्शनी का भ्रमण करें, प्रतिदिन सायं 6:00 बजे से 8:00 बजे तक आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं।

डॉ वी. सिवक कुमार ने लोगों से आह्वान किया कि वे प्रामाणिक खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीद करें तथा खादी एवं पी.एम.ई.जी.पी उद्यमियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।इस प्रकार की सहभागिता से लघु, सूक्ष्म एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय उद्यमिता सुदृढ़ होगी तथा आत्मनिर्भरता, सतत आजीविका और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी।

हरियाणा के राज्यपाल ने आरडी परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल असिम कुमार घोष ने हरियाणा लोक भवन में एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड और गणतंत्र दिवस शिविर में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन पर बधाई दी। राज्यपाल ने कैडेटों के संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण की सराहना की और कहा कि उनका चयन उनकी अनुशासन, चरित्र और समर्पण का प्रमाण है।

एनसीसी निदेशालय की 133 कैडेटों वाली टुकड़ी, जिसमें हरियाणा के 29 कैडेट शामिल थे, ने नृत्य, बैले और राष्ट्रीय एकीकरण प्रस्तुति के माध्यम से देश की संस्कृति का प्रदर्शन किया, जिसने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित किया।पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ (पीएचएचपीएंडसी) एनसीसी निदेशालय ने 17 एनसीसी निदेशालयों में से रनर-अप ट्रॉफी जीती और कई पदक तथा ट्रॉफियां हासिल कीं।कार्यक्रम में प्रधान सचिव दुष्यंत कुमार बेहेरा, अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल भारत मेहतानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विनीत गर्ग और उच्च शिक्षा महानिदेशक एस. नारायणण सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मेजर जनरल मेहतानी ने पीएचएचपीएंडसी एनसीसी निदेशालय की ओर से राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

पंचकूला को स्वच्छ और मॉडल सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम के ठोस कदम

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

नगर निगम पंचकूला द्वारा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं मॉडल सिटी बनाने की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त श्री विनय कुमार ने नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को सशक्त करते हुए अलीपुर स्थित एमआरएफ सेंटर (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी), झूरीवाला ट्रांसफर स्टेशन (डंपिंग ग्राउंड) तथा सेक्टर-26 स्थित एस्पिरेशनल टॉयलेट का फील्ड निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अलीपुर एमआरएफ सेंटर की वर्तमान स्थिति, निर्माण एवं उपयोग की प्रगति तथा आसपास की बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने एमआरएफ सेंटर तक पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।साथ ही, झूरीवाला ट्रांसफर स्टेशन को अलीपुर एमआरएफ सेंटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए, जिससे शहर के ठोस कचरा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि झूरीवाला क्षेत्र से खुले कचरे की समस्या समाप्त होने से स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी। श्री विनय कुमार ने इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर जोर देते हुए कहा कि अलीपुर एमआरएफ सेंटर पंचकूला के ठोस कचरा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके पश्चात नगर निगम आयुक्त ने सेक्टर-26 स्थित एस्पिरेशनल टॉयलेट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति, सोलर पावर, स्वच्छता व्यवस्था एवं दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को शीघ्र पूर्ण कर यह आधुनिक सार्वजनिक शौचालय आम जनता के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए।

पंचकूला में आयुष्मान भारत/चिरायु सर्जिकल कैंप सप्ताह का शुभारंभ

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

स्वास्थ्य विभाग, पंचकूला द्वारा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 2 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक जिले में आयुष्मान भारत / चिरायु सर्जिकल कैंप सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, में पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क एवं कैशलेस सर्जरी की विशेष व्यवस्था की गई है।

सिविल सर्जन डॉ मुक्ता कुमार ने बताया की उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकूला में इस सर्जिकल कैंप का विधिवत आयोजन किया गया है। अस्पताल प्रशासन, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा आयुष्मान प्रबंधन टीम द्वारा कैंप के दौरान पूर्ण समन्वय एवं तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है।

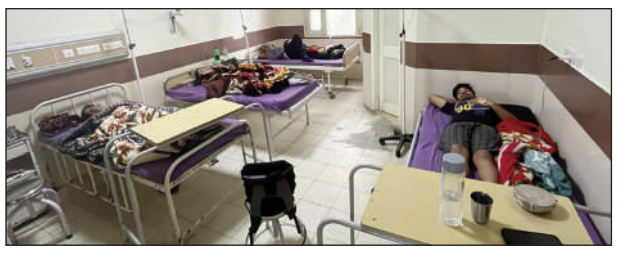

उन्होंने बताया की कैंप के प्रथम दिन 2 फरवरी को विभिन्न विभागों द्वारा सर्जरी की गई जिसमे 6 जनरल सर्जरी 3 लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी , 2 ओपन शल्य क्रियाएँ , 2 अन्य प्रक्रियाएँ, 2 ईएनटी सर्जरी, 2 नेत्र सर्जरी, 2 ऑथोर्पेडिक सर्जरी और 3 स्त्री रोग सर्जरी विभाग शामिल है ।

इसी प्रकार कैंप के दूसरे दिन आज तीन फरवरी को 7 जनरल सर्जरी , 2 लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी , 5 अन्य प्रक्रियाएँ, 2 ईएनटी सर्जरी, 5 नेत्र सर्जरी, 1 स्त्री रोग सर्जरी और 1 ऑथोर्पेडिक सर्जरी की गई । सभी सर्जरी आयुष्मान भारत/चिरायु योजना के अंतर्गत निःशुल्क एवं कैशलेस रूप से संपन्न की गई।उन्होंने बताया आगामी 4 से 7 फरवरी तक सर्जिकल कैंप की सुचारु कार्यवाही हेतु विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई है जिनमे विशेषज्ञ सर्जनों एवं एनेस्थीसिया टीम की निरंतर उपलब्धता, ऑपरेशन थियेटर (डळ) का 247 संचालन-सक्षम रखरखाव, प्री-ऑपरेशनल एवं पोस्ट-ऑपरेशनल वार्ड में अतिरिक्त बेड की उपलब्धता, दस्तावेज सत्यापन एवं लाभार्थी पंजीकरण हेतु समर्पित आयुष्मान हेल्पडेस्क, स्टेरिलाइजेशन, पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति और प्रत्येक विभाग में मरीज सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु हेल्प टीम की नियुक्त शामिल है।

संक्षिप्त-समाचार

ज्योतिष ज्ञान संस्था द्वारा आईबीसईए के सहयोग से भव्य मेगा अवॉर्ड फंक्शन का आयोजन किया गया

चंडीगढ़। कार्यक्रम में लगभग 100 सनातनी विद्वानों और साधकों ने सहभागिता की और इस विषय पर सार्थक संवाद हुआ कि कैसे ज्योतिष एवं विविध आध्यात्मिक विद्याओं के माध्यम से भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में अंकिता ने साझा किया कि हमारी संस्कृति हमें ह्लअहं ब्रह्मास्मिह्व का जो अर्थ सिखाती है, वह यह नहीं कि ह्लमैं श्रेष्ठ हूँह्व, बल्कि यह कि ह्लमैं भी उसी परम चेतना का अंश हूँ।ह्व याद रखिए कि ह्लमैं श्रेष्ठ हूँह्व आत्मविश्वास है, लेकिन ह्लमैं ही श्रेष्ठ हूँह्व अहंकार है। हम वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं।पूरी दुनिया एक परिवार है। हम गाय को माता कहते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, और मानते हैं कि कण-कण में ईश्वर है। हमारे शास्त्र कहते हैं ह्लयदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,ह्व अर्थात जब-जब समाज मार्ग से भटकता है, तब-तब धर्म स्वयं मार्ग दिखाने आता है। हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ मोबाइल ऐप्स, ए.आई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आध्यात्म हर युवा तक पहुँच रहा है। जेन-जी की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आज फेथ-टेक इंडस्ट्री का वैश्विक मार्केट साइज लगभग 65 बिलियन डॉलर, यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपये है। कई स्टार्टअप्स ने उल्लेखनीय फंडिंग जुटाई है और ई-पूजा, ई-प्रसाद तथा अन्य डिजिटल संसाधनों के माध्यम से हर घर तक सेवाएँ पहुँचा रहे हैं। भारत में इस समय 900 से अधिक स्पिरिचुअल टेक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, और कोविड के बाद डिजिटल आध्यात्मिक सेवाओं की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

फसली अवशेषों से सर्कुलर और कम-कार्बन पैकेजिंग पर पंजाब-हरियाणा की पहली क्षेत्रीय बैठक

चंडीगढ़। एग्री-फाइबर आधारित सर्कुलर और कम-कार्बन पैकेजिंग सप्लाई चेन को लेकर पंजाब-हरियाणा की पहली क्षेत्रीय गोलमेज बैठक हयात रीजेंसी मेंह्यअसरह्व और ह्यकैनोपीह्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। बैठक में पंजाब और हरियाणा सरकारों के अधिकारी, पल्प और कागज उद्योग के प्रतिनिधि तथा किसान संगठनों के सदस्य शामिल हुए। पंजाब सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब सरकार फसली अवशेषों के टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस तरह की चर्चाएँ और साझा मंच नीति-निमार्ताओं, उद्योगों और किसानों को बेहतर समझ विकसित करने में मदद करते हैं। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि औद्योगिक ढांचा सर्कुलर उत्पादन के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। यह संवाद हमें यह समझने में मदद करता है कि कृषि से बची सामग्री को कम-कार्बन पैकेजिंग की सप्लाई चेन में इस तरह शामिल किया जा सकता है, जिससे उद्योग और पर्यावरण दोनों को लाभ हो। असर की सीईओ विनुता गोपाल ने कहा कि यह संवाद किसानों के लाभ, जंगलों की सुरक्षा और कम-कार्बन सामग्री की ओर बदलाव के लिए एक अहम कदम है। कैनोपी की कंट्री डायरेक्टर श्रुति सिंह ने कहा कि फसली अवशेष उद्योग के लिए उपयोगी, कम-कार्बन और जलवायु जोखिमों का प्रभावी विकल्प हैं।

संसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कालका-अंबाला क्षेत्र के लंबे समय से लंबित रेल मुद्दे उठाए

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने आज दिल्ली में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कालका-अंबाला क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों से जुड़े लंबे समय से लंबित रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं के मुद्दे प्रमुखता से उठाए।

यह मुलाकात उन विषयों के संदर्भ में हुई, जिन्हें सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने एक दिन पूर्व संसद में उठाया था। सांसद ने बताया कि क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण रेल सेवाएं वर्षों से लंबित हैं, जिसके कारण आम नागरिकों, तीर्थयात्रियों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुलाकात के दौरान सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने विशेष रूप से ट्रेन संख्या 14887/14888 बारमेर-कालका एक्सप्रेस के पुनः संचालन की मांग रखी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन कोविड काल के दौरान बंद कर दी गई थी, जबकि यह कालका, चंडीगढ़ एवं हिमाचल क्षेत्र को राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और बारमेर जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली एकमात्र सीधी रेल सेवा थी। इसके बंद होने से कालका-अंबाला क्षेत्र के यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

इसके अतिरिक्त सांसद ने कालका से हरिद्वार एवं कालका से दिल्ली के लिए नियमित एवं किफायती यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने, कालका-अमृतसर नई ट्रेन सेवा शुरू करने तथा कालका-शिरडी और कालका-कटरा तीर्थयात्री ट्रेनों की साप्ताहिक आवृत्ति वर्तमान तीन दिन से बढ़ाकर कम से कम छह दिन करने की मांग भी रखी।

सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ये रेल सेवाएं केवल यात्रा सुविधा का विषय नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और धार्मिक यात्राओं से सीधे जुड़ी हुई हैं। सस्ती और नियमित रेल सेवाओं के अभाव में आम नागरिकों को महंगे निजी साधनों पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि इन सभी विषयों को सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने कल संसद में प्रमुखता से उठाया था। आज हुई मुलाकात के दौरान रेल मंत्री ने कालका-अंबाला क्षेत्र से जुड़े इन मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र कार्यवाही और समाधान का आश्वासन दिया।

सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जनहित से जुड़े इन विषयों पर उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा और वे तब तक इन मुद्दों को आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक क्षेत्र की जनता को इसका ठोस लाभ नहीं मिल जाता।

स्टैशफिन ने बजट 2026-27 के वित्तीय समावेशन और एमएसएमई-आधारित विकास पर मजबूत समर्थन की सराहना की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

केंद्रीय बजट 2026-27 उद्यमियों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक भरोसेमंद और उत्साहजनक संकेत है, जो भारत की विकास यात्रा में उनकी निर्णायक भूमिका को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। श्रुति अग्रवाल, सह-संस्थापक, स्टैशफिन का कहना है कि औपचारिक ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ करने, तरलता बढ़ाने और वित्तीय तंत्र को सरल बनाने के माध्यम से यह बजट छोटे व्यवसायों से जुड़ी उन चुनौतियों को संबोधित करता है, जो लंबे समय से उनकी प्रगति में बाधा बनी हुई थीं। डिजिटल एकीकरण पर विशेष जोर वित्त तक पहुंच को अधिक सहज बनाता है और एक पारदर्शी, प्रभावी तथा उद्यमी-अनुकूल इकोसिस्टम के निर्माण को गति देता है, जो नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण एक समावेशी और सशक्त अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखता है, जहां हर आकार के उद्यम स्पष्ट दिशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। एक स्थिर और पूर्वानुमेय वित्तीय वातावरण तैयार कर तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी का विस्तार करके यह बजट उद्यमियों को सतत विकास की ओर बढ़ने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है। कुल मिलाकर, यह दीर्घकालिक विकास और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने वाले एक जीवंत, अवसर-प्रधान इकोसिस्टम के निर्माण की स्पष्ट मंशा को दशार्ता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा लीड एजेंसी तथा लोक निर्माण विभाग, पंजाब सरकार के सहयोग से सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण एवं सड़क अभियांत्रिकी प्रथाओं पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला का किया आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा लीड एजेंसी तथा लोक निर्माण विभाग, पंजाब सरकार के सहयोग से आज चंडीगढ़ में सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण एवं सड़क अभियांत्रिकी प्रथाओं पर एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्र में सड़क सुरक्षा परिणामों को बेहतर बनाने हेतु कार्यरत वरिष्ठ नीति-निमार्ताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, अभियंताओं, योजनाकारों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाकर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना था। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अवधारणा है, जिसमें सड़क डिजाइन एवं प्रबंधन के केंद्र में मानवीय कमजोरी एवं संभावित त्रुटियों को रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपरिहार्य मानवीय गलतियों से मृत्यु या गंभीर चोट न लगे। यह दृष्टिकोण दुर्घटनाओं के लिए केवल सड़क उपयोगकताओं को जिम्मेदार ठहराने के बजाय, सुरक्षित अवसंरचना, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों तथा बहु-विषयक समन्वय के माध्यम से एक क्षमाशील एवं लचीले सड़क परिवेश के निर्माण पर बल देता है। इस अवसर पर पंजाब के लोक निर्माण विभाग मंत्री, श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने राजमार्ग सुरक्षा एवं अभियांत्रिकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र और राज्य के प्रयासों के तालमेल पर जोर दिया।

कार्यशाला का शुभारंभ एनएचएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी श्री राकेश कुमार के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु एक समग्र, अभियांत्रिकी-आधारित रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजमार्गों के डिजाइन में उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप मानव सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, वैज्ञानिक योजना तथा दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्यशाला को भारतीय प्रशासनिक सेवा की राज्य परिवहन आयुक्त एवं महानिदेशक, सड़क सुरक्षा (लीड एजेंसी), पंजाब सुश्री प्रणीत शेरगिल; भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, पंजाब सरकार सुश्री हरगुनजीत कौर; तथा भारतीय पुलिस सेवा के विशेष पुलिस महानिदेशक (यातायात), पंजाब श्री ए. एस. राय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संबोधित किया। अपने संबोधनों में वक्ताओं ने मजबूत संस्थागत समन्वय, आंकड़ा-आधारित निर्णय-प्रणाली तथा अभियांत्रिकी, प्रवर्तन एवं नीतिगत उपायों के एकीकृत क्रियान्वयन के माध्यम से सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं एवं गंभीर चोटों में निरंतर कमी लाने हेतु सड़क अभियांत्रिकी पद्धतियों, यातायात प्रबंधन तथा प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियाँ एवं विचार-विमर्श किए गए। एनएचएआई मुख्यालय के सलाहकार (सड़क सुरक्षा) श्री सुदर्शन के. पोपली ने राजमार्गों के सुरक्षित अभियांत्रिकी डिजाइन से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी तथा यह स्पष्ट किया कि सुरक्षित सड़क अवसंरचना एवं अग्रसक्रिय सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।भारतीय सड़क कांग्रेस के सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एवं सदस्य श्री स्वतंत्र कुमार ने नवाचारी परावर्तक समाधानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने प्रभावी संकेतकों, उच्च दृश्यता वाली सड़क चिह्नांकन व्यवस्था तथा यातायात सुरक्षा उपकरणों (रोड फर्नीचर) की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो वाहन चालकों की जागरूकता एवं मार्गदर्शन को बेहतर बनाते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की प्रोफेसर गीताम तिवारी ने ह्लरोड टू ट्रैफिक सेफ्टी 2030ह्व विषय पर एक ज्ञानवर्धक सत्र प्रस्तुत किया।उन्होंने सड़क सुरक्षा में स्थायी सुधार हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों एवं नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए योजना, प्रवर्तन एवं अवसंरचना समाधानों के सुव्यवस्थित एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। सेव लाइफ फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रबंधक श्री राहुल प्रकाश सिंह ने सुरक्षित राजमार्गों हेतु शून्य मृत्यु गलियारा संबंधी अभियांत्रिकी हस्तक्षेपों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने व्यावहारिक अध्ययन-उदाहरणों एवं प्रमाणित सुरक्षा उपायों को साझा किया। शून्य मृत्यु गलियारा की अवधारणा का उद्देश्य अभियांत्रिकी, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल एवं सामुदायिक सहभागिता के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को न्यूनतम करना है। यह एक साक्ष्य-आधारित मॉडल है, जिसने उच्च जोखिम वाले मार्गों पर मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्शाई है। कार्यशाला में एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्य सरकार विभागों के प्रतिनिधि, यातायात एवं राजमार्ग अभियंता, योजना विशेषज्ञ तथा सड़क अवसंरचना एवं सुरक्षा से जुड़े अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। यह कार्यशाला ज्ञान-साझाकरण, तकनीकी विमर्श तथा अंतर-एजेंसी सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी, जिसने राष्ट्रीय एवं वैश्विक सड़क सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप वैज्ञानिक, टिकाऊ तथा जन-केंद्रित सड़क अभियांत्रिकी प्रथाओं के प्रति एनएचएआई की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

इस प्रकार की पहलों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के सड़क नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, अधिक लचीला एवं आधुनिक गतिशीलता की जटिल आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।